पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक

समय माया

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569, 7804872701
Phone Fax: +91 731 2015827

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 08 अंक 32 प्रति सोमवार इंदौर, 10 से 16 मार्च 2014 पृष्ठ 8 मूल्य 2/- रुपए

केंद्रीय व राज्य सरकारों की बजट नौटंकी

पूंजीपतियों के इशारे पर अपनी कमाई की व्यवस्था

सत्ताधीशों को पूंजीपतियों से ही धन मिलता है, बजट भी वही बनवाते है

हर वर्ष अगले वित्तीय वर्ष के लिये सरकार चलाने अपना कमीशन अपनी कमाई किस मद से कितनी होगी को ध्यान में रखते हुए पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, बहुराष्ट्रीय कं. जिनसे मोटा कमीशन अगले बजट वर्ष में मिलता रहेगा, इसके लिये उनके इशारे पर उनके लाभ को सुनिश्चित करने के लिय करो, किस प्रकार कितना लगाया जाये, आयकर में कितनी छूट दी जाये, कस्टम और एक्साइज से चलकर, रेल किराये, भाड़ा आदि, राज्यों के विक्रय कर, आबकारी, रायल्टी, बिजली पानी, सड़कों व अन्य आय के स्त्रोतों पर कर की दरें निर्धारित की जाती है। ताकि उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कं. द्वारा सत्ताधीशों को मोटा कमीशन सतत मिलता रहे। सभी शासकीय विभागों को चलाने सरकार की साख बनी रहे, हर वर्ग के लोगों को खुश रखने, उनसे भविष्य में वोट पाकर सरकार बनाने की स्थितियां निर्मित की जाती है। हर शासकीय विभाग की योजनाओं, खर्चों से आय और अनुमानित राजस्व की आय में से अपनी कमाई और नियोजित, अनियोजित, खर्चों, नई-पुरानी योजनाओं के खर्चों और उससे भविष्य में वोट बैंक और अपने लाभ की व्यवस्था का नियोजन बजट में अगले वित्तीय वर्ष के लिये किया जाता है।

जनता के द्वारा चुने गये लोक प्रतिनिधि नेता, मंत्रीयों, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यह अच्छी तरह ध्यान में रहता है कि जो ये पांच वर्ष मिले है इसमें ही पुराने खर्चों को निकालने से लेकर, आगे के जीवन में अपने, अपने परिवार को चलाने के लिये सारे धन की व्यवस्था करना है, अन्यथा कोई भरोसा नहीं कि कब तक सरकार चले, दूसरा अगली बार टिकिट मिले न मिले, टिकिट मिल भी गया तो जीते या न जीते, इसलिये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, उनके सचिव मिलकर अपने मंत्रियों उनके सचिवों से लेकर नीचे तक सभी कमाई, कमीशन की व्यवस्था को जनहितों का नमा दिखाकर स्वहितों का पहले ध्यान रखा जाता है।

यही कारण है कि राजस्व की वसूली वाले कर विभागों और राजस्व को छोड़कर हर आबंटन जो केंद्र से राज्यों के आवंटन में भी वसूली के बाद आवंटन दिया जाता है। सारे बजट की रचना इस प्रकार की जाती है। जनहितों में खर्च किये जाने वाला हर रु. का 5 से 25 पैसे तक इनके हाथों में पुनः लौट आये, चाहे अनुदानों के माध्यम से, सेवाओं को मुफ्त में देने के माध्यम से, चाहे वो पूंजीपतियों को दिये जाने वाले लाभों में से कमीशन के तौर पर पहले आये या बाद, सर्वप्रथम पूंजीपतियों के लाभ बढ़ोत्तरी, उनकी इच्छाओं के अनुकूल, जनता से हो या सरकार का ध्यान रखा जाता है। महाघूर्त पूंजीपतियों, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, पिछले 30-40 वर्षों से पूरा पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय पिछले 15 वर्षों से अनेकों प्रदेशों का ऊर्जा मंत्रालय हांक और इच्छानुसार नचा रहे है। तैल, गैस, बिजली जबसे निजी हाथों में जाने लगी है, उनकी इच्छानुसार हर वस्तु की कीमतें निर्धारित होती है।

अमेरिका का रुस और उसके राज्यों की बर्बादी से अभी तक दिल नहीं भरा

अमेरिकी शह पर यूक्रेन लड़ने को तैयार था रुस से

अमेरिका, रुस से अभी भी भारी दहशत में है, षड्यंत्र रचता है रुस की बर्बादी के

पूरे विश्व में 1960-70 के दशक में दो महाशक्तियां हुआ करती थी यू.एस.ए. अर्थात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और संयुक्त सोवियत रुस गणराज्य। पूरी दुनिया के अधिकांश राष्ट्र इन दो ध्रुवों में बंटे हुए थे, जिस पर भी अमेरिका अपनी षड्यंत्रकारी नीतियां और युद्ध थोपता, सोवियत रुस उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से हर प्रकार की सहायता देता, जिसमें सैन्य सहायता में, जल, थल और वायु सैन्य सामग्री, हथियार, गोला-बारुद और सैनिकों तक को लड़ने भेजता था, जिससे अमेरिकी चालें या तो विफल हो जाती या उसे वहां मुंह की खानी पड़ती, वियतनाम जैसे राष्ट्र में अमेरिका ने नौ वर्ष युद्ध किया और अंत में वहां से भागते वक्त अपने हैलिकॉप्टर्स, युद्ध पोत तक को समुद्र में डुबोकर उसके सैनिक वहां से भागे, ईरान-ईराक से युद्ध में भी ईराक को, अमेरिका, तो ईरान को रूसी अप्रत्यक्ष तन-मन-धन से सहयोगी था। 9 वर्ष चले 1977 से 1986 तक चले इस युद्ध में दोनों ही राष्ट्र ने भारी तबाही देखी थी।

इसके बाद वहां मिखाइल गोर्वाचोव को राष्ट्रपति बनाया गया जो अमेरिका का सहयोगी था उसने पूरे संयुक्त सोवियत रुस गणराज्य

को खंड-खंड बिखेर 27 राज्यों में बदल दिया, इसके बाद भी अमेरिकी प्रशासन की 25-30 वर्ष बाद भी नियत नहीं बदली और दिल भी नहीं भरा, उसके समुद्री तटों पर चिपके राज्यों में छल, बल, धन से अपने पैर पसारने और रुस को घेरने के षड्यंत्र रचता रहा है, 7 वर्ष पूर्व में उसने चेचेन्या से रुस को लड़वाया, रुस को अमेरिकी हर चाल और उसके चारों तरफ उसी के राज्यों द्वारा की जा रही गतिविधियों पर नजर रहती हैं, जब उसके पड़ोसी राज्यों की गतिविधियां रुस के विरुद्ध षड्यंत्रों, जिसमें अमेरिका, नाटो शामिल होकर ज्यादा तकलीफें देने लगते हैं। स्वाभाविक है, रुस को बचने और अपनी सुरक्षा के लिये हथियार उठाकर युद्ध के लिये विवश होना पड़ता है, जैसा कि 2008 अगस्त में चेचेन्या और अभी युक्रेन के विरुद्ध करना पड़ा।

निःसंदेह रुस के 27 टुकड़े हो जाने के बाद भी वह अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली हैं, पर उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हैं।

इसलिये वह ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मंच पर हो-हल्ला नहीं करता है, रुस सामरिक रुप से मजबूत है। उसके साइबेरिया में प्राकृतिक खनिजों की जिसमें कच्चा तेल, गैस शामिल हैं आकूत संपदा है, जिस पर अमेरिका और नाटो की निगाहें हैं। इसलिये अमेरिका उसके पुराने राज्य जो अलग होकर राष्ट्र बन चुके हैं।

उन्हें धन, बल, छल से अपनी गिरफ्त में लेकर रुस को घेरने, उसे कमजोर करने में लगा ही रहता है, साथ ही अभी भी रुस अमेरिका की हड़प नीति का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुलकर विरोध करता है, जो अमेरिका और नाटो को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वह उसके व्यावसायिक व सामरिक गतिविधियों को न केवल ईरान, जार्डन आदि में रोक चुका है।

फसल बीमा अरबों रु. का प्रीमियम भर हड़प रही बीमा कं.

करो, रु. 12000 करोड़ के फसल बीमे से किसानों की क्षतिपूर्ति

नौटंकी थी, म.प्र. बंद, व्यापमं की जांच को सीबीआई से बचाने की शिवराज की

म.प्र. में 18-20 फर. से हुई भारी बरसात और ओलों ने पूरे प्रदेश के अधिकांश जिलों में रबी की फसल पककर कटने को जो तैयार खड़ी थी, पूरी तरह से बर्बाद कर दी, स्वाभाविक था, व्यक्तिगत स्तर पर मप्र के 80 लाख से ज्यादा किसानों के भविष्य को अंधकारमय बनाकर कर्ज में डुबो दिया। जिसे परिणामस्वरूप कई स्थानों पर किसानों ने आत्महत्या कर ली। निःसंदेह किसानों को इस घोर पीड़ा से उबारने के लिये मु.मं. शिवराज सिंह ने संवेदनशीलता दिखाई और किसानों को ढाढंस बंधाया, इसके विपरीत पूरा प्रशासन और मंत्री परिषद जानती थी कि लोकसभा चुनाव अप्रैल में घोषित हैं। मार्च के शुरु होते ही कभी भी चुनावी सूतक की आचार संहिता लग जाने से केन्द्र सरकार आस्तित्वहीन हो जायेगी और कोई निर्णय नहीं ले सकेगी, प्रदेशभर में भारी बारिश और ओलों से बर्बादी 18-19 फरवरी से ही शुरु हो चुकी थी जो रह-रहकर 1-2 मार्च तक चलती रही, पहली भारी बारिश और बर्बादी के बाद ही प्रशासन को किसानों की फसल की क्षति के आंकलन के आदेश दिए जा चुके थे, इसलिए प्रभावित जिलों की तहसीलों में आंकलन शुरु हो चुका था और 28 फर. तक हुए सर्वे से निष्कर्ष निकाले जा चुके थे रु. 5000 करोड़ से ज्यादा की फसल पूर्णतः बर्बाद हो चुकी है, इस बीच कांग्रेस ने 6 मार्च को व्यापमं घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए म.प्र. बंद करने की घोषणा कर दी थी। 4 मार्च 14 को चुनाव आयोग ने चुनावों के कार्यक्रम को घोषित करने के साथ ही चुनावी सूतक की आचार संहिता भी लगा दी थी,

(शेष 4 पर)

सभी भाजपा राज्य में बहुराष्ट्रीय कं. के भुगतान पत्रक पर कमीशन

मोदी प्रधानमंत्री, तो सब बहुराष्ट्रीय कं. की कठपुतली

कांग्रेस से ज्यादा घातक होगी, भाजपा की सरकार, गुलामी तेजी से लायेंगे

वर्तमान में राष्ट्र में मोदी के धुआधार चुनाव प्रचार से चारों तरफ के मोदी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा चारों तरफ जोरों पर है। उनकी जोड़ का अभी पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर कोई भी ऐसा सशक्त उम्मीदवार नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि पूर्वोत्तर, बंगाल, दक्षिण भारत के कई राज्यों में भाजपा की भूत और वर्तमान में ठोस उपस्थिति नहीं है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या तथ्य की भविष्य की दिशा निश्चित करने के लिये उसके भूत और वर्तमान के आंकलन से भविष्य निर्धारित होता है, यही तथ्य मोदी पर भी लागू होता है, मोदी के गुजरात की उन्नति में मोदी ने राष्ट्रीय-अंर्तराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कं. को आंख मींच कर गुजरात के औद्योगिकीकरण में, किसानों और खेती की जमीन की बर्बाद कर सहयोग कर रहा है, बिजली, पानी, सड़कों और जमीनों को उद्योगपतियों को रियायती दरों पर जनहितोंका बलाये तक रखकर उपलब्ध करवाया गया, बेशक औद्योगिकीकरण राष्ट्रोन्नति के लिये आवश्यक है। पर औद्योगिकीकरण के दुष्प्रभावों का किस प्रकार पूरा युरोप और अमेरिका व अन्य औद्योगिक रूप से भोग रहे हैं। किस प्रकार पूरी पृथ्वी के वायुमंडल को बिगाड़ा है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, दूसरी और मोदी भारतीय कं. जिसमें अंबानी, टाटा, बिरला व अन्य सैकड़ों की कठपुतली बन सबकुछ उनकी मनमर्जी और इशारों पर चलकर सारी नीतियों का निर्धारण कर रहा है। (शेष पेज 7 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

नोट से वोट सत्ता में पहुंचते ही वोटरों को गहरी चोट

लोकतंत्र में, लोक द्वारा चुने गये प्रतिनिधि सत्ता में पहुंचते ही, जिस लोक द्वारा चुने जाते है, उनके द्वारा चुना हुआ वह नेता मंत्री, फिर उसी लोक से प्राप्त करारोपणों के लोकधन से स्वः उद्धार में जुटकर उसी लोक का घोर शोषण करते हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का विश्वव्यापी दुर्गुण है, जिसके पीछे स्वयं वही जनता जिम्मेदार है, जो इन नेताओं मंत्रियों को नोट लेकर वोट देती है, वोट देते समय मतदाता यह देखता है कि कौन सा उम्मीदवार उन पर कितना धन खर्च कर वोट मांगने आया है। स्वाभाविक है जो नेता माफिया उम्मीदवार धन खर्च करेगा वह सत्ता में पहुंचते ही, निवेशित धन को ब्याज से कई गुना ज्यादा जनता से या जनधनसे वसूलेगा।

अब जबकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित हुये 66 वर्ष से ज्यादा हो चुके है। शिक्षा, संचार साधनों, रोजगार, व्यापार, सड़कों, स्वास्थ्य आदि का बहुत अच्छा विकास हो रहा है, स्थितियां और सामाजिक परिस्थितियां में भी काफी बदलाव हो चुका है। अब जनता के सामने अपने बहुमूल्य मताधिकार क लिये कुछ नोटो में बिकने की मजबूरी भी नहीं है, जो मजबूरी 30-40 वर्ष पहले थी, फिर संचार साधनों टीवी, मोबाइल आदि ने जागरूकता काफी बढ़ा दी है, जिससे ग्रामीणों से लेकर शहरों की झुग्गी बस्तियों जहां बड़े अपराधी नेता नोट और शराब की नदियां बहाकर मतदान अपने पक्ष में करवा लेते हैं। चुनकर सत्ता में पहुंचने के बाद वे ही अपराधी नेता जो नोट, शराब व अन्य वस्तुओं पर धन खर्च करते हैं वे उसकी उन गरीबों से ही भारी अप्रत्यक्ष करारोपण से वसूले गये धन को भारी भ्रष्टाचार में हजम कर जाते हैं। वे भले ही गेहूं, चावल आदि रु. 1 किलो में बांटकर तत्काल में भले ही गरीब हितैषी बनने की नौटंकी करें, पर यथार्थ में उसके अंतर की वसूली डीजल-पेट्रोल, ईंधन गैस, बिजली की कीमतें बढ़ाकर कई गुना ज्यादा करके यथार्थ में गहरी चोट ही पहुंचाते है। जिसका सीधा असर सबसे ज्यादा उन गरीबों पर ही ज्यादा पड़ता है, जिन्होंने नोट लेकर उन अपराधियों, नेताओं को वोट दिया था। प्रकृति का सीधा सा गणित है कि जो लिया यहीं से लिया, जो लिया उसे यहीं देना भी है। फिर जिसने लिया है वही देगा भी, फिर जो देता है वह लेगा भी और जो देगा, वह लेगा भी, चाहे इंसान हो या भगवान, सामने से नहीं लेता तो पीछे से अप्रत्यक्ष करो के रूप में, रिश्वत के रूप में लेगा, चाहे फिर वह सरकार हो जिसमें भी आपके ही द्वारा चुने गये प्रतिनिधि है। लोकतंत्र में मतदाताओं को यह समझना जरूरी है कि यदि वे नोट लेकर वोट देंगे तो स्वाभाविक रूप से महंगाई की गहरी चोट खाने के लिये भी तैयार रहना चाहिए। भ्रष्टाचार हो रहा है, वो होगा ही क्योंकि जिसने अधिकतम वोट पाने के लिये नोट बांटे है, शराब बांटी है और यथार्थ में वोट खरीदकर जीता है तो भ्रष्टाचार से ही कमायेगा। जब भ्रष्टाचार ही नेता, मंत्री, विधायक, सांसद से लेकर पार्षदों और सरपंचों की कमाई है, खर्च पूरा करने का साधन है तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही, उसकी भी गहरी चोट जनता को ही लगेगी।

यदि जनता चाहती है कि महंगाई न बढ़े, भ्रष्टाचार न हो तो जनता को वोट के लिये नोट, शराब, कूकर, साड़ियां, कंबल, टीवी, लेपटॉप, मोबाइल बांटने वालों से बचें और अगर मजबूरी में ऐसी भेंट स्वीकारना ही पड़ जाए तो कम से कम ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के नेता को वोट तो कभी न दे, ताकि वो नेता जीतने के बाद जनता को गहरी चोट न दें।

प्रकृति का नियम है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। यदि नोट लेकर वोट दोगे जैसा कि भारतीय लोकतंत्र का पुराना इतिहास रहा है, तो फिर हर कदम चुने हुये नेता, मंत्री, बांटे गये धन को तरह-तरह के प्रपंचों से चाहे तो फिर 1 रु. किलो में गेहूं, चावल बांटकर जनता को भिखारी बनाकर अपनी वसूली और मोटे कमीशन के लिये करोड़ो किसानों, छोटे व्यापारियों को बेरोजगार बनायेंगे, जानबूझकर आयोडाइज्ड नमक खिलायेंगे, चाहे फिर जनता को ब्रेन हेमरेज की क्यों न हो।

इस संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि लोकतंत्र में हर व्यस्क नागरिक का कर्तव्य है कि वह जाति, धर्म, निर्धन, धनवान सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग गुण, बुद्धि विवेक से तत्काल के लालच को छोड़कर भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए।

सुषमा की जगह, साधना सिंह लोकसभा प्रत्याशी!

पूरे देश में आम चुनाव की तैयारियों के लिए राजनीतिक चौसर बिछाने का काम चल रहा है। राज्यवार प्रत्येक राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि अपनी अपनी गोटियॉ बिठाने की जुगत में आत्ममुग्ध होकर साम,दाम,दण्ड,भेद हर तरह से तैयारियों में जुटे है । प्रत्येक राज्य में राजनीतिक और समाजिक समीकरण अलग अलग है। इस पूरे चुनाव में देश के दो प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने प्रतिस्पर्धा में है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। वहां पर क्षेत्रीय दलों का और क्षेत्रीय भाषी और व्यक्ति विशेष लोगों का अपना-अपना प्रभाव है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में जैसे उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश,राजस्थान,दिल्ली ,हरियाणा,उत्तरा खण्ड,बिहार झारखण्ड,पंजाब आदि राज्यों में भाजपा का जनाधार दिनों दिन बढ़ रहा है तो कांग्रेस का विरोध चरम पर है। कांग्रेस कार्यकाल में निरन्तर दस वर्षो से सत्तासीन होने के कारण महंगाई और दिन पर दिन उजागर होते रहे घोटाले इसके प्रमुख कारण रहे है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेन्द्र मोदी का ओजस्वी भाषण और व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार के कारण मीडिया में चलने वाली खबरों के कारण एक ऐसा माहौल बन गया है मानों श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके है। चुनाव एक औपचारिकता मात्र बची है। इस दिव्यस्वप्न में हर भाजपा का कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि हर कोई अपने और अपने परिवार के सदस्यों के सहारे संसद भवन में पहुंचना चाह रहा है। वहीं आज कांग्रेस में कोई ओजस्वी प्रवक्ता श्री नरेन्द्र मोदी के टक्कर का मैदान में नहीं है,जो हर तरह से राजनीतिक बयान रूपी चौसर पर अपना सही मोहर फेंक सके। सभी राजनीतिक दलों के दावे स्वयं गंगाजल की तरह पवित्र और समाज का अगुआ और दूसरे दल को गंदे दल-दल का भंडार ,जन विरोधी और देश का लुटेरा साबित करने में लगे हुए है। इस लोकतांत्रिक भारत देश में अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राजनीतिक सीढ़ी सबसे उपयुक्त माध्यम होती है। अगर राजनीति के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख श्री लालू यादव के समतुल्य मुख्यमंत्री पतिदेव श्री शिवराज सिंह चौहान हों तो ऐसा मौका सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। ऐसा ही कुछ पूर्ववर्ती घटनाओं,वर्तमान परिस्थितियों के कारण प्रतीत होने लगा है कि विदिशा लोक सभा सीट पर एक रणनीति के तहत श्रीमती सुषमा स्वराज के स्थान पर श्रीमती साधना सिंह प्रत्याशी बन सकती है। पन्द्रहवीं लोक सभा की सदस्य एवं लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज से पूर्व श्री शिवराज सिंह पांच बार सांसद चुने जा चुके है। वर्ष 1991 के आम चुनाव में श्री अटल बिहारी बाजपेयी के त्याग पत्र देने के बाद मानों शिवराज सिंह चौहान को विदिशा लोकसभा सीट बिरासत में मिल गयी थी। आज शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री है और विदिशा और बुधनी विधान सभा से विजयी प्रत्याशी रहे है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी की तरह शिवराज सिंह चौहान विदिशा विधान सभा से त्याग पत्र दे चुके है। अर्थात आने वाले दिनों में विदिशा लोकसभा और विधान सभा का उपचुनाव एक साथ होंगें। सूत्र बताते है कि श्री शिवराज सिंह चौहान लोक सभा सीट पर अपनी पत्नी श्रीमती साधनासिंह को भाजपा की ओर से प्रत्याशी बनवाना चाहते है। इसके लिए एक पूर्व से सुनियोजित योजना पर काम चल रहा है। राजनीतिक गलियारों के

जानकार श्री शिवराज सिंह चौहान और श्रीमती सुषमा स्वराज के संबंधों की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मन के अन्दर की कड़वाहट को भली भांति पहचानते है। इसके कई कारण भी है। श्री शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक गुरू श्री सुन्दर लाल पटवा श्रीमती सुषमा स्वराज के धुरविरोधी खेमें के है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है। जब मण्डीदीप नगर पालिका के चुनाव में प्रत्याशियों का चयन हो रहा था तो चयन में सुषमा स्वराज अपने खेमें के प्रत्याशियों के लिए अड़ गई थी और तुलात्मक दृष्टि से सुषमा स्वराज का वर्चस्व भारी पड़ा था,तो श्री पटवा को निर्वाचन में उम्मीदवार बनने वाले अपने कार्यकर्ताओं के सामने लज्जित होना पड़ा था। इसी प्रकार भोजपुर में श्री पटवा के विरोधी मौन रहते थे परन्तु सुषमा स्वराज की वजह से वे सभी मुखर हो गये। विधान सभा चुनाव के दौरान श्रीमती सुषमा स्वराज विदिशा से पूर्व विधायक श्री गुरूचरण सिंह की पुत्री श्रीमती सुखप्रिय कौर राष्ट्रीय सचिव महिला मोर्चा ,को प्रत्याशी बनाने के पक्ष में थी इसके विरूद्ध श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निकट कार्यकर्ता मुकेश टंडन का नाम आगे कर दिया । जब इसका पार्टी स्तर पर और कार्यकर्ताओं में विवाद बढ़ा तो शिवराज सिंह चौहान स्वयं विदिशा से प्रत्याशी बन गये। अर्थात श्रीमती सुषमा स्वराज को अघोषित रूप से राजनीतिक मात दे कर एक तरह से वॉक ओवर कर दिया। शिवराज सिंह चौहान विदिशा विधान सभा क्षेत्र से त्याग पत्र दे चुके है और पूरे विदिशा क्षेत्र में अपनी पत्नी श्रीमती साधना सिंह को दल बल के साथ सक्रिय कर दिया है। स्वयं भी विदिशा संसदीय क्षेत्र में एक एक दिन में 10-10,12-12 गॉव घूम कर माहौल बनाने में लगे हुए है,और लोक लुभावन घोषणाऐं खेत खलिहानों में जाकर जन समूह के बीच कर रहे है। ताकि जनता को अपने प्रभाव और पत्नी के नाम पर वोट बटोरे जा सकें ,और श्रीमती सुषमा स्वराज के नाम को जनता में नगण्य किया जा सके। जनता में ऐसा माहौल बन जाय कि श्रीमती साधना सिंह और श्री शिवराज सिंह चौहान ही भरोसेमंद,जनहितैषी और संकटमोचक साबित हो जायें है। साधना सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार वार्तालाप ,व्यवहार और प्रचार -प्रसार हो रहा है उससे साफ संकेत मिलते है कि श्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा की सीट किसी तरह अपने कब्जे में करना चाहते है। श्रीमती सुषमा स्वराज के क्षेत्र में उनकी निष्क्रियता,निश्चिन्तता और उनका जनता और कार्यकर्ताओं में अलग-अलग माध्यमों से विरोध का माहौल तैयार करा रहे है ,ताकि भविष्य में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा यह संदेश देने का कार्य किया जा सके,और उन्हें बताया जा सके कि गत लोक सभा चुनावों में 4 लाख वोटों से आपको जनता ने एक तरह से वॉक ओवर दिया था वह जनता अब आपको 4 हजार वोट भी देने वाली नहीं है। जब श्रीमती स्वराज के विदिशा के अतिरिक्त अन्यत्र सुरक्षित सीट के लिए सुझाव मांगा जायेगा तो भोपाल से प्रत्याशी बनाये जाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में भोपाल से सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी को उनकी अधिक आयु और वृद्धावस्था के नाम पर उनका टिकिट काटे जाने की पूरी संभावना बलवती हो जायेगी है। इस कार्य के लिए एक रणनीति के तहत गोपनीय तरीके से शनैः शनैः कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। दूसरा कारण एक और भी है,गत विधान सभा चुनावों में श्री शिवराज सिंह ने जिस प्रकार अपनी लगभग हारी हुई सीट को धन और तंत्र के दमपर जीत में परिवर्तित कराया उसकी रातों रात भारी कीमत भी चुकानी पड़ी अर्थात विदिशा के किसी भी आम मतदाता से पूछा जा सकता है कि चुनाव में प्रति वोटर पैसा और शराब किस कदर बॉटी गई तब कहीं जाकर मात्र 16 हजार वोटों से जीत हासिल हो पाई,जबकि वे आज प्रदेश के यशस्वी जननायक मुख्यमंत्री के नाम से देश में प्रसिद्ध है। इसी प्रकार लोकसभा चुनाव में बहुत प्रशासनिक तंत्र के साथ मिलकर मेहनत करना पड़ेगी यदि विधान सभा जैसा माहौल बना तो भारी भरकम खर्चा कौन करेगा?श्रीमती सुषमा जी के नाम पर शिवराज मेहनत और पैसा क्यों खर्च करेंगें? विधान सभा खर्च के अनुपात में लोकसभा में इस प्रकार के खर्च के लिए कम से कम सौ करोड़ रूपये खर्च करने पड़ेगें। विदिशा लोकसभा में दो विधान सभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक है। तथा कई बूथों पर श्री शिवराज चौहान के कट्टर समर्थक कार्यकर्ता भी विरोध करेंगें। इन परिस्थितियों में श्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा के चुनाव में अपनी पत्नी श्रीमती साधना सिंह को पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी बनवाने का सशक्त प्रयास कर रहे है। सूत्र बताते है कि यदि लोकसभा चुनाव में श्रीमती साधना सिंह को प्रत्याशी बनाया जाता है तो बुधनी विधान सभा चुनाव की तरह कांग्रेस की ओर से कमजोर प्रत्याशी उतारा जायेगा और श्रीमती सुषमा स्वराज प्रत्याशी बनती है तो कांग्रेस की ओर से श्री राहुल गॉधी की गाईड लाईन का नाम लेकर एक मजबूत और प्रभावशाली प्रत्याशी मैदान में उतारा जायेगा। सूत्र बताते है कि इसका खाका श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर तैयार कर लिया गया है। श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के आपसी मधुर संबंधों को पार्टी का हर कार्यकर्ता जानता है। सभी जानते है कि श्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री निवास कभी नहीं जाते है बल्कि हर बार दिग्विजय सिंह के भोपाल आगमन पर श्री शिवराज सिंह चौहान श्री दिग्विजय सिंह से मिलने उनके श्यामला हिल्स स्थित सरकारी बंगले पर स्वयं मिलने जाते है। और चरण वंदन कर आर्शीवाद प्राप्त करते है। अब यदि श्रीमती सुषमा स्वराज प्रत्याशी बनती भी है,तो यह भी संभव है कि श्री दिग्विजय सिंह अपने पुत्र अथवा किसी परिवार के सदस्य अथवा नजदीकी को मैदान में कांग्रेस की ओर से लोकसभा प्रत्याशी बनाकर उतार दें। मध्य प्रदेश यह हाई प्रोफाईल लोक सभा सीट पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। इस लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम ,खाती, किरार, और ब्राह्मण समाज का वर्चस्व है। यह सामाजिक समीकरण चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सभी समाजों में श्री शिवराज सिंह चौहान अपना प्रभाव जमाने के राजनीति छल, मोहमाया, संम्मोहन हर फन में माहिर खिलाड़ी है। अगर चुनाव प्रचार में शिवराज सिंह चौहान की ऑधी चली तो मध्यप्रदेश में श्रीमती सुषमा स्वराज की स्थिति सुश्री उमा भारती जैसी हो सकती है और श्रीमती साधना सिंह की श्रीमती सुषमा स्वराज जैसी राष्ट्रीय स्तर की छवि बन सकती है। इस पूरी चौसर के खिलाड़ी और पांसे फैकने वाले मध्य प्रदेश भाजपा में यथावत है। बस जैत गांव के भैया के एक इशारे का इन्तजार है। अगर ऐसा हुआ तो मध्यप्रदेश में एक बार फिर नया इतिहास रचा जायेगा। और देश नया आगाज होगा । देश में एक नया संदेश होगा पत्नी के साथ राजनीति क्षितिज पर सीढ़ी चढने वाले अकेले श्री लालू प्रसाद यादव ही नहीं श्री शिवराज सिंह चौहान भी गिने जायेंगे।

भाजपा ने किसान मोर्चा से करवाई रेल रोको की असफल नौटंकी

खाद्य सु.व मा.अधि. से होने वाली बर्बादी से ध्यान हटाने का षड़यंत्र

पूंजीपतियों की रखेल, मूखेरे जानवरों की पार्टी, अपनी वसूली के लिए छल रही है किसानों को

भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को पूंजीपतियों, बहुराष्ट्रीय कं. के हाथ में सौंपने के लिये कांग्रेस और भाजपा दोनों ही ने न केवल कमर कस रखी है, वरन् बहुराष्ट्रीय कं. के हितों को साधने में इन गिद्ध नेताओं और भ्रष्ट जालसाज नौकरशाही ने अनेकों कानून बना जनता का चहुंदिशि बहुविधि शोषण करने की व्यवस्था कर दी है, इन घाघ कांग्रेसी, भाजपाईयों और दोनों के संप्रग और राजग के सहयोगी दलों के भेड़िये नेताओं ने ऐसे अनेकों कानूनों पर अंगूठे लगाकर देश की जनता को हर कदम नोंचने-खसोटने की अगले 200-500 वर्षों तक की व्यवस्था है, जहां जनता का शोषण सड़क से लेकर रसोई और थाली तक किया जा सके, जनता केवल सांस ले किसी प्रकार रूखा-सुखा खाकर इनका वोट बैंक बनी रह सके। संभवतः इस शोषण और जनता को लूटने का सबसे पहला कानून के इशारे पर टाटा केमिकल्स लि. को घाटे से उबारकर बचाने के लिये, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने बनाय था। आयोडीन नमक कानून 1972 जिसमें साधारण नमक को आयोडीन मिलाकर बेचे जाने की व्यवस्था की, इसकी आवश्यकता मात्र लगभग 50 लाख लोगों को थी, आवश्यकता न होने पर भी पूरे देश की 68 करोड़ जनता पर 1972 में थोप दिया गया था, उस समय 25 पैसे में 5 किलो खड़ा नमक मिलता था, परंतु 1972 में कानून बनने के बाद यह 50 पैसे किलो बिकने लगा था, इस अधिनियम के लागू होते ही पहले ही वर्ष में यह कंपनी लाभ में आ गई थी। उसके बनाये इस कानून का परिणाम, अनावश्यक रूप से व जबरदस्ती नमक के साथ आयोडीन खाने के रूप में सामने आने के बाद भी न केवल स्वास्थ्य मंत्रालय भी कमीशन हजम करने के कारण चुप्पी मारे बैठा है, वरन् वहीं भाजपा जो विपक्ष में रहने तक आयोडीन नमक के विरूद्ध हल्ला मचाती रही, परंतु सत्ता में आने के बाद मोटे कमीशन के चलते चुप रही। अब जबकि 4 अगस्त 11 से खाद्य सुरक्षा व मानक अधि. 06 से लागू हो गया, जिसको लोकसभा में पास करते समय मोटी रिश्वत के कारण आंख भींच अंगूठा लगा दिया, जबकि इस कानून में सबसे ज्यादा दो तरफ लूट किसानों के साथ ही होना है, इसके 5 अगस्त 14 के बाद मप्र में लागू होने के बाद किसान अपनी उपज खेत-खलिहान से मंडी नहीं ले जा पायेगा। बहुराष्ट्रीय कं. उसकी उपज और उत्पादन को खेत-खलिहान जाकर खरीदेगी। स्वाभाविक है तो उसे कम से कम कीमत में ओन-पौने भाव में खरीदेगी जिससे उसकी लागत भी नहीं निकलेगी। उसकी व उसके परिवार की न्यूनतम मजदूरी और लाभ की बात तो बहुत दूर ऐसी अवस्था में किसान वर्ष दो वर्ष खेती करेगा बाद में कर्ज के बोझ को कम करने के लिये या तो आत्महत्या करेगा या ओने-पौने दाम में जमीन बैचकर भागेगा। इन सबसे किसानों का ध्यान हटाने के लिये ही भाजपा ने अपने घूर्त नेताओं को आगे कर, किसानों के लिये केन्द्र सरकार द्वारा गठित आयोग की शर्तों को लागू करने के लिये, किसान मोर्चा से पूरे देशभर में रेल रोको आंदोलन की असफल नौटंकी करवाई गई, जो पूरे देश में असफल रही।

भाजपा को सत्ता मिलते ही उसके मुख्यमंत्री, मंत्री, कांग्रेसियों के भ्रष्टाचार और लूट-खसोट को कई मामलों में पीछे छोड़ चुके है। और यथार्थ में ये भुखेरे जानवरों की पार्टी बन पूंजीपतियों यथा टाटा, अंबानी, बिरला, जेपी एसोसिएट्स, सहारा, आईटीसी, हिन्दुस्तान लीवर आदि की रखैल बन उनके हितों में, जनता की बर्बादी की दास्तां लिखने में जुटे है और सत्ता में रहकर न केवल सार्वजनिक संपत्तियों वरन जनहितों को अपना मोटा हिस्सा डकार निलाम कर रहे हैं। इसके लिये वो जनता के विरूद्ध जनता को ही हथियार बनाकर नौटंकी करवाते रहते है। जैसा कि किसान मोर्चा के द्वारा, किसानों की वास्तविक बर्बादी से ध्यान हटाकर रेल रोको आंदोलन करवाया गया।

29 गांवों को नगर निगम सीमा में शामिल करने का षड़यंत्र

मात्र भूमाफियाओं के फायदे के लिये शामिल किये जा रहे है गांव

गांवों की जमीनों को ओने-पौने हथियाकर करेंगे अरबों रु. की कमाई

इंदौर नगर निगम की सीमाओं में 29 गांवों को शामिल करने के षड़यंत्र में मुख्यमंत्री कार्यालय से मुख्य सचिव आदि से लेकर नीचे नगर निगम और पंचायतों तक सभी शामिल है। यह गांवों को नगरों की नगर निगम की सीमाओं में शामिल करने का षड़यंत्र केवल इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर में ही नहीं वरन् पूरे प्रदेश और देश में चल रहा है, यह खेल दिल्ली में और उसके आस-पास के क्षेत्रों में चलते हुये आधी शताब्दी गुजर चुकी है, जिसका मूल उद्देश्य होता है, गांवों की कृषि भूमि को कानूनी चंगुल से मुक्त करवाकर शहरी विकास के लिये उपयोग में लाकर हजारों गुना कमाई, न केवल नेता, भूमाफिया, जिलाधीशों से लेकर सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर नगर निगमों के अदने से सफाइ कर्मचारी तक सबको आर्थिक लाभ मिलता है।

सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी जिन्होंने जनहित में उच्च न्यायालय में अनेको याचिकाएं प्रस्तुत की है। 29 गांवों के प्रकरण की याचिका भी इन्होंने ही दायर की है।

मास्टर प्लान के अनुसार नगर निगम की सीमा में 29 गांवों को शामिल करने की योजना है तो 29 गांवों को ही शामिल किया जा रहा है, उच्च न्यायालय में प्रकरण पहुंचने के बाद, उच्च न्यायालय ने न केवल इस प्रकरण को संपन में वरन जब इसके तथ्यों की जांच की गई, तो न केवल अनेकों कमियां सामने आई, इन सब कानूनी पेचीदगियों और औपचारिकताओं को पूरा न करने के पीछे भी दूसरे अन्य षड़यंत्र जो सीधे आर्थिक लाभ प्राप्ति की तैयारी में रचे गये है।

गांवों को नगर निगम सीमा में शामिल करने की घोषणा मात्र से सभी संबंधित शासकी विभागों जिसमें जिलाधीश के साथ ही सभी उपजिलाधीशों, सहायक जिलाधीशों तहसीलदारों से लेकर पटवारियों तक की उनके अधिकारों में वृद्धि हो गई, स्वाभाविक है ग्रामीणों की उनकी जमीन की कीमत के भाव आसमान छूने लगे, जिससे लेन-देन और खरीद-फरोख्त में भी करोड़ों की कमाई होगी ही, भूमाफियाओं कालोनी माफियाओं के साथ-साथ अन्य उनसे जुड़े जालसाज घूर्तों को भी मोटी कमाई के अवसर मिलते ही, बेशक इन सबकी घूर्त चालों में फंसेगी और लूटेगी वह आम जनता जो वर्षों से अपनी छत और मकान का सपना संजोये बैठी है। नगर निगम पालिकाओं से पुराने शहर की साफ-सफाई, बिजली या रात्रि पथ प्रकाश की व्यवस्था तो वर्षों से संभलती नहीं, इन नये गांवों को शामिल करने के बाद 5 वर्षों तक शामिल किये गये गांवों में, भूमाफियाओं द्वारा अपना घूर्तता के चलते बड़े-बड़े विज्ञापन देकर प्लाट, फ्लेट, मकान बैच दिये जाते हैं। उसके बाद वर्षों तक वहां पानी, बिजली, नालियों, सड़कों, स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था नहीं होती, और गांवों को जमीन का वर्षों बाद मालूम चलता है कि सरकारी भूमि, नजूल, नदी, नाले, वन भूमि आदि थी, जो कि अवैध रूप से बाद में वर्षों बाद ग्राम एवं नगर निवेश विभाग को अगर मोटी रिश्वत नहीं दी जाती है, तो वह उसे पूरा अवैध करार कर देता है। वही हाल जिलाधीश नगर निगम आदि भी करते हैं।

म.प्र. के गृह निर्माण मंडल, विकास प्राधिकरण भी जमीनों का अधिग्रहण इन गांवों-जमीनों का अधिग्रहण कर कालोनियां काटते हैं। उस वक्त भी भू अधिग्रहण का अरबों रु. के भुगतान में खूब खुलकर करोड़ों की बंदरबांट की जाती है। साथ ही शुरु हो जाता है, पार्षदों, नेताओं, विधायकों, गांवों के सरपंचों, पंचों, आयुक्त, जिलाधीश, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदारों, पटवारियों, दलालों की लूट और वसूली का खेल।

जमीनों की खरीद-बिक्रीसे लेकर विकास के नाम, सड़कों, पुल-पुलियाओं, स्ट्रीट लाइट, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन के ठेकेदारों, विभागों की लूट और वसूली का जो 10 से 30-40 वर्षों तक पूर्ण विकसित होने तक लगातार चलता है। जिसमें हर अदने से कर्मचारी, चपरासी, बाबू से लेकर निगमायुक्त से लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री, सचिव तक गाहे-बगाहे वसूली चलती रहेगी।

विश्वभर में न केवल भारत, म.प्र., इंदौर, भोपाल, जबलपुर में या अन्य सभी शहरों में बढ़ते शहरीकरण उसके परिणामस्वरूप खड़े होते, बढ़ते कांक्रीट जंगल न केवल पर्यावरण बिगाड़ रहा है, न केवल हरियाली वरन् पूरे मालवा के हर जिले की कृषि योग्य काली दूमट भुरभुरी मिट्टी जो विश्व में कृषि के लिये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, भूमाफियाओं, कालोनाइजरों, सत्ता में बैठे धूर्त, जालसाज, गिद्धों जो न केवल नेता, मंत्री, आईएएस, आईपीएस से लेकर एसएएस अधिकारियों कर्मचारियों के षड्यंत्रों के परिणाम स्वरुप जिसमें मोटी कमाई और शीघ्र धनाढ्य होने की महत्ताकांक्षाओं के चलते बर्बाद की जा रही है। जिससे मात्र मनुष्यों की लालची प्रवृति भर संतुष्ट हो रही हो तत्काल में, पर दीर्घकाल में अपनी ही स्वास्थ्य, स्वच्छ जलवायु की समस्याओं को बढ़ा रहा है, साथ अन्य जलचर, वनचर, नभचरों को समाप्त कर रहा है।

मप्र लो. भ्रष्टाचार निर्माण विभाग- रिश्वतों का सेतु

लो.नि. सेतु संभाग भ्रष्टों और जालसाजों का अड्डा

का.यं. रा.ना.मिश्रा ऐतिहासिक महाभ्रष्ट, जालसाज और बदतमीज

इंदौर के तीन इमली चौराहे 28 फरवरी 2014 को बन रहे रिंग रोड को फ्लाई ओवर की छत का क्रांकीट स्ले व टपक गया, इंदौर सेतु संभाग के कार्य पालन यंत्री आर.एन. मिश्रा पुराना महाभ्रष्ट, जालसाज रहा है। यह घूर्त मिश्रा यहां पिछले 15 वर्ष से ज्यादा समय से सहा. यंत्री के रूप में इंदौर संभाग-1 और 2 में रह चुका है। जहां न केवल भारी भ्रष्टाचार के लिये कुख्यात रहा वरन् अपने कार्य. यंत्रियों, अधीक्षण यंत्रियो और प्रमुख अभियंताओं की शिकायतें करने, उन्हें परेशान करने के लिये भी जाना जाता है। इसके साथ ही इसके नीचे के उपयंत्रियों, बाबुओं और चपरासियों के साथ भी बहुत ही बदतमीजी से व्यवहार करने के कारण सभी दुखी रहते है। इसकी भ्रष्टाचार करने, उसके छुपाने सब उच्च अधिकारियों जिसमें अपने वरिष्ठ अधिकारियों में पहले का.यं., अ.यं., मु.अ. प्रमुख अभियंता, सचिव, प्रधान सचिव और पूर्व के लोक निर्माण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तक इसकी बतत्तमिजियों, शिकायतों, भ्रष्टाचार आदि के कारण इसका नाम तक सुनना नहीं चाहते थे, इसलिये मंत्री विजयवर्गीय ने इसका स्थानांतरण कर दिया था, जिसे इसने भारी जोड़-तोड़ और धन खर्च कर पुनः इंदौर करवाया था। अभी भी जब इसके द्वारा बनाये जाने वाले पुल को ढह जाने के बाद अपने आप को बचाने के लिये ट्रक को टकराने की झूठी कहानी गढ़ी, जबकि उसके चारों तरफ के रहवासियों और दुकानदारों ने ही इसकी इस मनगंढ़त कहानी की स्वयं को और ठेकेदार कंपनी को बचाने की कोरी बकवास थी, भोपाल स्थित सेतु परिक्षेत्र के मु.अ. पटेल ने भी उसी दिन से इसको बचाने के लिये इसकी मनगंढ़त कहानी को पुल ढहने को आधार बनाने की कोशिश की। हाला फिलहाल इसको निलंबित किया है, जबकि ताकि इस मामले को निलंबन के शीतल में डालकर ठंडा किया जा सके। इस बीच इसको बचाने और निलंबन का समाप्त कर पुनः सक्रिय किया जा सके, जबकि इसके द्वारा बनाई गई रूचि सोया प्लांट के सामने वाली मांगलिया की सड़क में 3 माह बाद ही दरारें पढ़ गई थी, इसके सारे कार्यों का इतिहास निकाला जाये तो इसने हर कदम भ्रष्टाचारों का अंबार लगा रखा है। इसके संभागक के अंतर्गत सारे ओवर ब्रिज व अन्य पुलों की ही समीक्षा की जाये तो इसके द्वारा निर्माण किये जा रहे निर्धारित समय से दोगुना, तिगुना समय पूरा होने के बाद भी पूरे नहीं हुये, क्योंकि पूरे मप्र के सेतु संभागों में सबकी लागत बढ़ाकर कमीशन खाने की आदत है। जानबूझकर अतिक्रमण बिजली के खंभे आदि का सहारा लेकर काम अटका कर ठेकेदार को लागत का डेढ़ गुना से दो गुना भुगतान करवाकर उसमें हिस्सा डकारना चाहते हैं। जब निलंबन हो गया है तो भोपाल की अपेक्षा जिला ग्वालियर पदस्थ किया जाए ताकि जांच प्रमाणित न कर सकें।

'समय माया' के स्वामित्व एवं अन्य विवरण के संबंध में

घोषणा पत्र

फार्म-4 (नियम 8 देखिए)

1. प्रकाशक का स्थान	: इंदौर
2. प्रकाशन अवधि	: साप्ताहिक
3. मुद्रक का नाम	: अजमेरा एस.पी. कुमार
(क्या आप भारत के नागरिक हैं)	: हां
(यदि विदेशी हैं तो मूल देश)	: -
पता	: 299 अम्बेडकर नगर इंदौर (म.प्र.)
4. प्रकाशक का नाम	: अजमेरा एस.पी. कुमार
(क्या आप भारत के नागरिक हैं)	: हां
(यदि विदेशी हैं तो मूल देश)	: -
पता	: 299 अम्बेडकर नगर इंदौर (म.प्र.)
5. प्रधान संपादक का नाम	: अजमेरा एस.पी. कुमार
(क्या आप भारत के नागरिक हैं)	: हां
(यदि विदेशी हैं तो मूल देश)	: -
पता	: 299 अम्बेडकर नगर इंदौर (म.प्र.)
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझीदार हों :	: नहीं

मैं **अजमेरा एस.पी. कुमार** एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

दिनांक : 10 मार्च 2014

हस्ताक्षर
अजमेरा एस.पी. कुमार
(प्रकाशक के हस्ताक्षर)

साप्ताहिक समय माया

सूचना आयोग, सत्ताधीशों के लिये अपनो को उपकृत करने का अड्डा बना

भ्रष्टों को बचाने फिर बैठा दिये, भ्रष्ट आई.ए.एस.

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा न्यायिक व्यवस्था से हो सूचना आयुक्त फिर भी एक भी नहीं, फिर पूर्व की तरह मजाक बना देंगे सू. अ. अधिनियम 05 का

पूरे भारत में सूचना अधिकार अधिनियम-05 का को लागू हुऐ 9 वर्ष पूरे होने जा रहे है, इसके विपरीत न केवल केन्द्र सरकार वरन् राज्य की सरकारों, चाहे वो कांग्रेस, भाजपा, सपा, जदयू किसी की भी हो, सबने इस कानून का खुलकर मजाक उड़ाया वरन् उसे अपनों को उपकृत करने के अड्डे के रूप में विकसित कर लिया गया। केन्द्र की कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टीयों के गिरोह ने भी केन्द्रीय सूचना आयोग में ऐसे चुन-चुन कर अपने खास लोगों को उपकृत किया ताकि उन्हें मोटे वेतन, गाड़ीया, बंगले देकर सरकार के विरूद्ध जाने वाली हर सूचनाओं, जानकारियों और रिकार्ड को न देने के लिये आवेदक को टरका दे। भारत सरकार का केन्द्रीय कार्मिक व व्यक्तिगत, दुख निवारण मंत्रालय ने इस कानून को लागू करने से लेकर हर वर्ष अरबों रु. इस अधिनियम को इसकी धारा 4 के अंतर्गत-17 बिंदुओं की जानकारी विभागीय इंटरनेट साइटों पर डालने और उसके उन्नयन के लिये हर राज्य सरकार के विभागों को भेजता है, जो पूरी राशि कागजों पर औपचारिकता में पूरी करके हजम कर ली जाती है।

यही कारण है कि केन्द्र के ही सभी विभागों और उपक्रमों ने 9 वर्ष बाद भी इस धारा का पालन करते हुये सारी जानकारी को ऑनलाइन इसलिये नहीं किया कि भ्रष्टाचार से धन वसूली में कोई रूकावट न आये फिर इसमें चाहे प्रधान कार्यालय हो या आयकर, कस्टम एक्साइज, के.लो. नि.वि., ऊर्जा, कृषि, उद्यानिकी, वन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, श्रम, डाक तार, संचार आदि। यही हाल देश के 29 राज्यों और 7 केन्द्र शासित राज्यों का भी रहा।

भले ही मप्र सरकार अपनी पीठ थपथपाकर आईटीआर का पुरूस्कार ले आये परंतु इस अधिनियम को भोथरा और पंगु बनाने से लेकर सभी विभागों की जानकारियों को धारा 4 के अंतर्गत, ऑनलाइन नहीं किया गया, दूसरी ओर सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने वालों को समय पर पूरी और सही जानकारी दे दी जाये तो आखिर आवेदक क्यों पहली और निराकरण होने पर दूसरी अपील लगायेगा। न पहली अपील करने का स्पष्ट अर्थ है कि विभागीय लोक सूचना अधिकांश ने जानकारी के आवेदन का जवाब ही नहीं दिया, यदि दिया तो अत्याधिक पैसे मांगे या जैसा चाहा गया था, नहीं दिया गया। इसलिये लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध उसके वरिष्ठ अधिकारी को अपील की गई, यदि प्रथम अपीलीय अधि. ने उसका न्यायपूर्ण तरीके से आवेदक की समस्या का निराकरण कर दिया होता जिसके पास सूचना आयुक्त की तरह पूरे अधिकार हैं, तो उसे दूसरी अपील के लिये बाध्य ही नहीं होना पड़ता, पर प्रथम अपीलीय अधिकारी को उसे फंसाने, उलझाने वाली जानकारी देने धारा 7 (6) के अंतर्गत 30 दिन में जवाब न मिलने या टरकाने की स्थिति में न केवल चाही गई जानकारी मुफ्त में देने के साथ ही धारा 19 (8) व के अंतर्गत 250/- प्रतिदिन तक का आर्थिक दंड अधिरोपित कर देता तो जिसके प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अधिकार है तो दूसरी अपील की नौबत ही नहीं आये। मप्र सूचना आयोग अपने गठन से लेकर वर्तमान तक केवल सत्ताधीशों के लिये ऐसे भ्रष्ट, जालसाज, आई.ए.एस, आईपीएस व अन्य पत्रकारों को उपकृत करने का अड्डा बन कर रह गया है, जिनके एहसानों को मुख्यमंत्री या सत्ताधीश न केवल उतारना, उन्हें 2 से 5 वर्ष तक सत्ता सुख देने के साथ ही अपने कुकर्मों, भ्रष्टाचार के दस्तावेजी सबूतों को आवेदक के हाथ में जाने से रोकने 2 से 4-5 वर्ष तक जानकारी आवेदक न पहुंचने देने में सहयोग करें और अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने में सहयोग करें। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त पीपी. तिवारी, दूसरे इकबाल अहमद और अब तीसरे मुख्य सूचना आयुक्त के डी खान इसके जीते जागते सबूत हैं।

सबसे पहले सूचना आयोग में दो इंडियन-एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी पी पी तिवारी और इकबाल अहमद थे, तिवारी के सेवानिवृत्ति के बाद इकबाल अहमद मु.सू.आ. का पद भार ग्रहण कर लिया था, उस समय एक महाभ्रष्ट जालसाज इंडियन क्राइम प्रोटेक्शन सर्विस अधिकारी दिनेश जुगरान थे, पत्रकार ज्यादा शोर-शराबा न करें, एक पत्रकार महेश बाजपेयी को भी सूचना आयुक्त के पद से नवाज दिया गया था, इन सब भ्रष्ट जालसाजों ने न केवल कानूनी प्रक्रियाओं का पालन तो दूर, अपनी अनावेदका से खूब वसूली के बदले आवेदकों को डांटना, फटकारना, बदतमीजी दिखाने के साथ ही सामने बैठे अनावेदक दाता अधिकारी को मान-सम्मान देकर, आवेदकों को तिरस्कार भी बुरी तरह से करके, जानकारी न मांगने, जानकारी का क्या करोगे, क्या मिलेगा तक करते थे।

जब इनकी इन सच्चाइयों को समय माया ने जोर-शोर से प्रकाशित किया तो सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर जुलाई 12 में स्पष्ट कहा था कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति न्यायिक व्यवस्था में कार्य कर रहे या सेवा निवृत्तों में से की जानी चाहिए जिन्हें न्यायिक प्रक्रिया का ज्ञान हो। इन सब तथ्यों के विपरीत मप्र सरकार के मु.मं. शिवराज ने फिर उच्च न्यायालय के आदेश पर, मुख्य सूचना आयुक्त अन्य आयुक्तों के पदों के लिये विज्ञापन भी दिया आवेदन भी बुलाने की नौटंकी पूरी की और पुनः 8 वर्ष पुराने ढर्रे पर चलकर अपनी मनमर्जी से दो इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी केडी खान और एच एल त्रिवेदी, एक आईपीएस एस.आर. सिंग को पत्रकारों का मुंह बंद रखने दो खास भांड पत्रकारों जे.के. शर्मा और आत्मदीप को सूचना आयुक्त बना दिया जो पुराना इतिहास दोहराते हुए सरकार को बचाते हुये उन्हें सीधे अपीलों के निराकरण कर पूर्व की तरह इतिहास बनायेंगे।

म.प्र. वाणिज्यकर अधिकारियों, कर्मचारियों की घोर कमी से परेशान

कर चोरी, जालसाजियां, वसूली बढ़ रही है शासन मौन

फार्म 49, 51 व अन्य फार्मों से कर चोरी की घटनायें बढ़ाने, स्वयं प्रशासन जिम्मेदार

म.प्र. वाणिज्यिक कर विभाग में पिछले 12-15 वर्षों से अधिकारियों, कर्मचारियों की काम के बढ़ते बोझ से कमी महसूस की जा रही है, लगातार व्यापार और व्यापार करने के तरीकों में बढ़ोत्री के साथ बदलाव आ रहा है, बेशक कीमतों के बढ़ने से कर प्राप्ति में भी हर वर्ष बढ़ोत्री हो रही है परन्तु उसी अनुमात में कर चोरी के कारण, कर की वास्तविक वसूली का प्रतिशत घट रहा हैं, जिसके पीछे प्रशासन का निकम्मापन और आयुक्त का ढीलापन भी हैं, वैसे भी वर्तमान आयुक्त अमित राठौर येन-केन प्रकारेण अधिकतर समय कार्यालय से दूर रहकर पूरा कर रहे हैं। विभाग में सैकड़ों कर्मचारी अधिकारी हर वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

फिर विभाग में ही अनेकों शाखायें, जिसमें आडिट विंग, एंटी इवेजन विंग, आइटीआर आदि भी खुल चुकी हैं। इसके विपरीत 432 स.वा.क. अधि. के पदों पर मात्र 164 ही है। निरीक्षकों के 300 पद और उपायुक्त के 18 पद खाली हैं। 30 जांच चौकियों पर भी अधिकांश पद खाली हैं। स्वाभाविक है, हर कार्य स्टाफ की कमी से प्रभावित हो रहा है। इसलिए प्रतिदिन करोड़ों रु. की कर चोरी शातिर व्यापारी कंपनियां आसानी से कर रही हैं। फिर एंटी इवेजन विंग भी हर जिले में एक होना चाहिए पर दो-दो संभागों में एक विंग हैं, पूरे म.प्र. के 51 जिलों में मात्र 5 विंग है। जो कि पूर्णतः कर चोरी रोकने में असक्षम हैं। जबकि हर जिले में एक विंग होना चाहिए जो सक्षमता से कर चोरी रोक सकें। स्टॉफ की कमी से न केवल कर चोरी को बढ़ावा मिल रहा है, वरन भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है, बेशक कंम्प्यूटराइजेशन और ऑनलाइन कर संग्रहण, पंजीयन से छोटा भ्रष्टाचार रुका है, तो इससे सी फार्म, फार्म 49, 51 व अन्य फार्मों से कर चोरी और जालसाजियां बढ़ी हैं। जिसका उदाहरण स्वरुप एजेंट सुरेश गोयल जिसने करोड़ों रु. की सी फार्म के अवैध बिक्री से स्वयं कमाई करके करवाई जिसमें वृत्त क्र. 5 की फार्म नियो कॉर्प इंटरनेशनल का नाम सबसे ऊपर रहा, सी फार्म की जालसाजियों में पकड़ा गया। सुरेश गोयल है। मात्र एक नाम है, जिसे भी अधिकारियों-कर्मचारियों को बचाने के लिए लीपापोती की प्रक्रिया उच्चस्तर पर चल रही हैं, वह अरबों रु. का घोटाला भले ही पूरा खुले न खुले परन्तु भविष्य में ऐसी जालसाजियों को रोकने की भी पूरी ठोस व्यवस्था नहीं की जा रही है, इसके मूल में टाटा कंसलटेंसी द्वारा मोटे कमीशन पर बनाये गये वाणिज्यकर के साफ्टवेयर भी हैं। जिसमें 5 वर्षों के बाद भी छोड़ी गई त्रुटियां, कमियां, शासन के निकम्मेपन के कारण दूर नहीं की जा रही है।

खई है रे कसम हमने

खई है रे कसम हमने
देश को गुलाम करने की,
अई जा रे उड़ के गोरा परदेशी
कमा संभाल लूटने की
बेरोजगार करी दे,
खेती छुड़ाई ले,
जर, जंगल, जोरू सब तेरी है,
सब तू लेई जा रहे आकर
परवाह नहीं हमें डूबने की,

खई है, रे कसम हमने
देश को गुलाम करने की,
अई जा रे उड़ के गोरा परदेशी
कमान संभाल लूटने की

आंसू हमने देखे नहीं
गरीब की आंखों में
वो कैसी गरीबी है,
जिसमें भूख के लिये
आंख में आंसू नहीं,
कमीशन देई जा हमे तो तू,
गुलाम बनाई के सब लूट लेई जा तू
खई है रे, कसम हमने
देश को गुलाम करने की
अगर जनता ने हमे चुन ही लिया है
सत्ता हमे सौंप ही दिया है
तो कमीशन खाना हमारा धर्म है,
5 वर्ष ही तो लक्ष्मी का करम है,
जितना लूट सके लूट लेई रे
वरना अंत काल पछतायेगा
सत्ता जायेगी छूट रे
खई है रे, कसम हमने
देश को गुलाम करने की
खेत बैच दे,
खलिहान बैच दे
मातृभूमि बैच दे
इस देश का हर इंसान बेच दे
अपने कमीशन के लिये
सत्ता में रहते
देश का हर सामान बेंच दे,
कल रहा न रहा
अपनी आत्मा से
चुकता ईमान बेंच दे
खई है, रे कसम हमने
देश को गुलाम करने की

- कवि, अजमेरा एस.पी. कुमार
इंदौर (म.प्र.)

रु.12000 करोड़ के फसल बीमे से किसानों की बर्बादी की क्षतिपूर्ति

पेज 1 का शेष

स्वाभाविक था केन्द्र सरकार नियमित कार्य करने और मांग पूरी करने का अधिकार खो चुकी थी, यह भाजपा सरकार और म.प्र. का प्रशासन अच्छी तरह जानता था, इन सबके विपरीत 6 मार्च को किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए म.प्र. बंद करने का क्या औचित्य था। इस नौटंकी का मात्र इतना औचित्य था कि जनता की भले ही बर्बादी हो, परन्तु कांग्रेस जो व्यापमं घोटाले के विरुद्ध आंदोलन कर सीबीआई की मांग करने जा रही है, जिसमें अधिकांश मंत्री, विधायक, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता सिद्ध हो चुकी है, उन्हें बचाने के लिए मामला सीबीआई के हाथ न चला जाये, अन्यथा जनता के सामने जो पोल खुलेगी वो तो ठीक है, परन्तु अधिकांश मंत्री विधायकों, अधिकारियों को नहीं बचाया जा सकेगा, इसलिए किसानों की बर्बादी के मुआवजे के नाम पर स्वयं ही आंदोलन की नौटंकी कर डाली। भले ही म.प्र. की जनता, व्यापारियों का नुकसान हुआ तो हुआ, इससे इन भाजपाई धूर्तों को क्या फर्क पड़ता है। कम से कम इन्हें तो इस बात की खुशी हुई कि कांग्रेस बंद का आह्वान कर जनता का ध्यानाकर्षण नहीं कर पाई, दूसरा इनके विरुद्ध सीबीआई को व्यापमं की जांच हाथ नहीं लगी।

दूसरी ओर किसानों की क्षतिपूर्ति का जहां तक सवाल है, तो प्रश्न यह भी उठता है कि म.प्र. सरकार ने किसानों की रबी की फसल का जो रु. 12000 करोड़ का बीमा करवाया था, उसकी प्रीमियम क्याक ईं अधिकारी, वित्त विभाग, कृषि विभाग का डकार गया, या किसी खास चहेते एजेन्ट ने डकार ली, मु.मं. शिवराज तो केन्द्र से मात्र रु. 5000 करोड़ मांग रहे हैं। रु. 12000 करोड़ तो उससे ढाई गुना ज्यादा है उससे वसूली कर आसानी से किसानों की बर्बादी की भरपाई की जा सकती है, या ऐसा है, कि भरपाई तो बीमे से कर ही ली जायेगी रु. 5000 करोड़ अगर केन्द्र से मिल ही गया तो भाजपा के मंत्री परिषद के खर्चों के काम आ जायेगा, बंदरबांट कर ली जायेगी। इस तथ्य के साथ ही जब सारी राष्ट्रीकृत बैंकों से किसानों के क्रेडिट कार्ड जारी हुए हैं। जिनमें कृषि ऋण ही महत्वपूर्ण तथ्य है और कृषि ऋण देते समय बैंकर्स सन् 1980 से फसल बीमे को किसानों के खाते में नामे डालते आ रहे हैं। यह बात दूसरी है कि अभी तक किसानों को बैंकों द्वारा बीमे की किस्त काटने के 34 वर्ष बाद भी किसानों की फसल की बर्बादी पर उनकी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया, जबकि सभी बैंकर्स को किसानों की तत्काल क्षतिपूर्ति करवाना चाहिए और वसूली करने की अपेक्षा उसके ऋण में समायोजन कर आधिक्य को उसके बचत खाते में जमाकर उसके खर्चे पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि बीमा करने का मतलब ही है कि किसान को उसकी लागत और कुल प्राप्ति का भुगतान बीमा कं. को करना चाहिए, केन्द्र के वित्त मंत्रालय के बीमा विभाग को निर्देशित करना चाहिए कि वह किसानों को जिनके खाते में फसल ऋण पर बीमा किशत काटी जाती है राज्यों के पटवारी, कृषि विभाग और तहसील के आदेश की पुष्टि पर 1 माह में भुगतान करें, ताकि किसानों पर ऋण का बोझ न पड़े और निराशा में आत्महत्या न करें, किसानों की आत्महत्या में घोर निराशा के साथ ही ऋण का बोझ सबसे ज्यादा परेशान करता है। यदि म.प्र. सरकार का कृषि मंत्रालय फसल बीमा करवाता है और अरबों रु. की प्रीमियम का भुगतान कर रहा है, तो क्यों, क्या मात्र बीमे की किशत में करोड़ों का कमीशन डकारने के लिये। कृषि विभाग का संचालक डी.एन. शर्मा ऐसे सभी कामों में अरबों का कमीशन अपने उच्च अधिकारियों को हिस्सा बांटने के साथ डकार जाता है। जब फसल बीमा की प्रीमियम किसानों के खाते से बैंकर्स काटते हैं तो किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर बैंकर्स से क्षतिपूर्ति पर पूरी फसल की कीमत मिले और दूसरा सरकार का कृषि मंत्रालय अगर प्रीमियम दे रहा है, तो उसके द्वारा भी कुल फसल की कीमत की क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। यदि दोनों बीमे मिल जाये तो फिर किसानों की लागत, मेहनत और लाभ तीनों की आसानी से भरपाई की जा सकती है।

महाभ्रष्ट, जालसाज, डकैत, लूटेरे, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को

हर 3 वर्ष में पदोन्नतियां, सभी लाभ व अन्य सुविधाएं

राज्यों के सरकारी, कर्मचारी अधिकारियों को 25-30 वर्ष के बाद भी पदोन्नतियां नहीं

भारतीय प्रशासनिक सेवाओं अर्थात आईएएस यथार्थ में इंडियन एब्यूसिंग सर्विस, जो देश के असली खुदा है। जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों से लेकर केन्द्र व राज्य सरकार के मंत्रियों विधायकों, सांसदों तक को सत्ता की शतरंज की बिसात पर अपनी अंगुलियों से नचाने और हांकते हैं, जिनके पास सारा सरकारी धन जो जनता से वसूला और लूटा जाता है को जनता के जनहितों के नाम से कैसी बंदरबांट की जाती है वह कोई इनसे सीखे। जबकि ये किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं होते, इसके विपरीत हरामखोर जालसाजों की फौज हर विभाग के शीर्ष पर बैठती है और हर प्रकार से अरबों रुपए प्रतिवर्ष की कमाई से लेकर, केन्द्रीय मंत्रालयों में बैठे ये धूर्त चुपचाप लाखों करोड़ रुपए हजम कर जाते है।

समय माया इन हरामखोर, मोटी चमड़ी के महाधूर्त जालसाजों जो बड़े अपराधियों ठगो, जालसाजों जैसे कि सुब्रतो राय सहारा आदि इनके सामने कहीं नहीं लगते, ये जो टूकड़े मंत्रियों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसदों, विधायकों, महापौरो को डाल देते हैं। वो चुपचाप इसी पर गुजर बसर करते हैं। ये आईएएस इस राष्ट्र की सबसे खतरनाक भ्रष्ट, जानसाज और लूटेरी कौम राष्ट्र को 30 से 35-38 वर्ष तक ने केवल लूटती है, वरन् राष्ट्र की सत्ता को अपनी अंगुलियों पर नचाती है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केन्द्र व राज्यों के मंत्री उसकी शतरंज की बिसात पर बैठे राजा, बजीर, हाथी, घोड़े और पैदलों से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसको जब चाहते है बैठाते है, जब चाहते है खेल से बाहर कर देते है। जनता उनके लिये कीड़े-मकोड़े के अतिरिक्त कोई औकात नहीं रखती। ये सत्ता के सारे सुख भोगते हैं, समय पर 3-3 वर्ष में पदोन्नतियां, गाड़ी, बंगले, नौकर-चाकरों की फौज जिलाधीश के रूप में जिले के बेताज बादशाह बन कर ऐशो-आराम, अय्याशी की जिंदगी के सार भोग भोगते हैं। सारे नियम-कानून इनकी जेब में पिछाड़ू पड़े रहते है। इन्हीं के कारण 20,000 से ज्यादा प्रशासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत 15 से 25 वर्ष पुराने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित नहीं किये जा रहे है, क्योंकि पूरे प्रदेश के 500 से ज्यादा विभिन्न मंत्रालय से लेकर जिलों में बैठे इन्हीं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के बंगलों पर 5 से 25 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की फौज कार्यरत रहती है। उनके हाथों से निकल जायेगी मात्र इसलिये ये एब्यूसिंग सर्विस अधिकारियों की लॉबी उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भी उन्हें नियमित नहीं कर रही, यही हाल प्रदेश के अधिकांश विभागों के 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों जिसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स से लेकर एसएएस, बाबुओं चपरासियों तक की फौज भी शामिल है, जिन्हें 20-25 वर्षों में एक भी पदोन्नति नहीं मिली, दूसरी सुविधाओं की तो बात तो बहुत दूर है। ये इंडियन एब्यूसिंग सर्विस अधिकारी अपने आप को सदैव ही आई एम सेफ मानकर चलते हैं। अपने पद के अधिकार संपन्नता के दम पर, जहां पदस्थ होते हैं, उस स्तर पर कुल आवंटित निधि का 10 से 40 प्रतिशत तक धन हजम कर जाना, एडीएम, एसडीएम, कलेक्टर, सचिव आदि के पदों पर हजारों करोड़ का खेल कर लेना बहुत मामूली होता है। जिसमें कालोनी माफियाओं, भूमाफियाओं, खनन माफियाओं से लेकर कार्पोरेट क्रिमिनल्स को संरक्षण देकर ये अरबों करोड़ की कमाई कर के हजम कर जाते हैं। यथार्थ में भ्रष्टाचार की संरचना, वसूली और हिस्सेदारी की बांटा-बूंटी ये ही करते है।

वही हाल इंडियन पुलिस सर्विस बनाम इंडियन क्राइम प्रोटेक्शन सर्विस की भी है। इन अधिकारियों में कोई भी आईपीएस अधिकारी कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाये तो न केवल सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति जो न केवल बेनामी वरन दूर के रिश्तेदारों और अपने यहां के नौकरों-चाकरों से लेकर अपने यहां के पालतु जानवरों के नाम तक से संपत्तियों के मालिक है। सभी बड़े ठगों, जालसाजों, सटोरियों, अपराधियों उच्च स्तरीय अय्याशी के अड्डों, जुआ घरो, स्मगलरों, काले धंधेबाजों से लेकर थानों के प्रभारियों से भी महीना वूसली करते हैं। शासन के स्पष्ट आदेशों के बाद भी क्यों ये शातिर घूर्तो की फौज 31 दिसम्बर तक हर वर्ष अपनी संपत्तियों के घोषणा पत्र सरकार या अपने उच्चाधिकारियों और विभागों को नहीं सौंपती, इन्हें भी अपने आका गृह सचिवों, प्रधान सचिव, गृह मंत्री आदि को अच्छी जगह पोस्टिंग के लिए एक मुश्त राशि बाद में मासिक रायल्टी चुकानी होती है। इन्हीं के संरक्षण में 90% कार्पोरेट क्राइम्स पनपते, फलते और फूलते है। आम आदमी घूंट-घूंट कर जीता हुआ मरता रहता है। दूसरी और अपराधी, ठग, भूमाफिया, सटोरिये, जुओं घर संचालक, चकला संचालक, अवैध शराब के अड्डे, खनन माफिया वसूली बाज गुंडे बदमाशों की फौज इन्हीं के महीना बांट एवं आराम की जिंदगी जीती रहती है। वहीं आम सिपाही, हेड कांस्टेबल, सहायक उपनिरीक्षक, निरीक्षक आदि जो सामान्य वर्ग में होते है। 10-10 वर्षो मैदानी कर्तव्यों का निर्वहन बिना साप्ताहिक छुट्टियों,अच्छे निवास, अन्य सुविधाओं के लिये तरसते हुये 12-14 घंटे तक कर्तव्यस्थ रहते है, जबकि दूसरी तरफ एक बार आईपीएस की परीक्षा पास करने के बाद ये सभी केन्द्रीय सेवा के अधिकारी न केवल नियमित हर तीन वर्ष में पदोन्नतियां, निवास के लिये अच्छे बंगले, वाहनों, 5 से 10 कांस्टबलों तक को अपने बंगलो पर रखते हैं। ऐशो आराम और अय्याशी पूर्व जीवन जीते हुये दो-पांच अरब से लेकर हजारों करोड़ रु. इकठ्ठा कर लेते हैं। जैसे कि पुरूषोत्तम सोमकुंवर, गांधी आदि। इसके विपरीत सीबीआई, लोकायुक्त, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो जैसी संस्थायें अपने मौसेरे डकैत भाइयों पर 99.9 प्रतिशत मामलों में हाथ नहीं डालती, क्योंकि ये ही आईपीएस व राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी ही लोकायुक्त, आ.अ. अन्वेषण, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, एसटीएफ, एंटी टेरर स्क्वॉड आदि में होते है। इन अन्वेषण लोकायुक्त संगठनों में वे ही पुलिस वाले अधिकारी जाते हैं, जो फील्ड में रहकर काफी बदनाम हो चुके होते है। भ्रष्टाचार, लूट, वसूली के आरोपों अपराधों की सलिप्तता के कारण इन्हें शाखाओं में भेज दिया जाता है। ये सब भी पूंजीपतियों और सत्ताधीशों के इशारों पर ही नाचते और प्रकरण मजबूत हल्के, कमजोर करते हैं। कार्पोरेट क्रिमिनल्स के संरक्षण दाता उन्हें बचाने और सुरक्षा देने का कार्य भी करते है।

आईएफएस अर्थात इंडियन फारेस्ट ईटिंग सर्विसेज, भारतीय वनों को कटाई, वनों की जमीनों को भूमाफियाओं, कालोनी, खनन माफियाओं को सौंप अवैध कमाई जो कि हजारों रु. प्रतिमाह और कीमत से चलकर हजारों करोड़ तक में होती है। पिछले 30 वर्षों में मप्र में जहां कभी 4-5 आईएफएस ही पूरे मप्र के रेंजों से लेकर मुख्यालय में बैठे है। एक तरफ आईएफएस जैसे बढ़ते गये, वैसे-वैसे दूसरी तरफ मप्र में वन प्राणी वनों में वृक्ष, वन क्षेत्र वनोपज, यहां तक कि बीट गार्ड, बाबु, रेंजरों की संख्या तक घटती गई पूर्व में वन विभाग में स्थायी सर्वेयरों की नियुक्ति हर रेंज में होती है जो नियमित रूप से वनों के सर्वे कर, वनोपज, वन प्राणी, वन क्षेत्र, वृक्षों आदि की संरक्षण तक पर नजर रख अपने कार्यालय को सूचित करती थी। स्वाभाविक था कि उससे इन आईएफएस गिद्धों को वन संपदा नोंचने, खसोटने में भारी परेशानी होती थी। इसलिये उस पद हो की समाप्त करवा दिया गया। यहां भी राज्य सेवा के रेंजरों, उप रेंजर से लेकर बीट गार्ड तक अधीक्षक से लेकर बाबु, चपरासियों को 15 से 20 तक कार्य से पदोन्नतियां और अन्य सुविधायें नहीं मिल पाती थी। जबकि इन हरामखोर, जालसाजों को हर 3-3 वर्ष में पदोन्नतियां व अन्य सुविधायें मिलती रहती है। पर इन पर भी लोकायुक्त, आ. अन्वेषण विंग या सीबीआई अनेको अपराधों और वन संपदा की अवैध खरीद, पट्टे पर कृषि भूमि खनन माफिया अवैध जंगलों की कटाई के साथ, राष्ट्रीय-अर्न्तराष्ट्रीय जैसे कि विश्व वन्य प्राणी निधि से मिलने वाला अमेरिकी डॉलर 2000 करोड़ जिसकी भारतीय मुद्रा में एक लाख 30000 करोड़ होती है, मिलती है। जिसका एक पैसा नीचे खर्च नहीं होता। प्रधान मुख्य वन संरक्षक से लेकर नीचे वन मंडलाधिकारी तक ही सब डकार जाते हैं। वहीं हाल विश्व खाद्य संगठन, पर्यावरण मंत्रालय, वन विकास निधि, हर वर्ष का हजारों करोड़ का पौधा रोपण, वन ग्रामों के विकास आदि का सारा पैसा, कागजों के जंगलों में आंकड़ों के उत्पादन में ही खर्च हो जाता है। वनों की संपदा का दोहन कर हजम करने में इनका कोई सानी नहीं है। 20 वर्षों में कोई भी जांच नहीं कर पाया।

आधार कार्ड नाम, पता बतायेगा ना कि इतिहास

आधार कार्ड अपराधियों, आतंकवादियों, घुसपैठियों को देगा कानूनी संरक्षण

कोई भी जालसाज, अपराधी कभी भी कहीं से आधार कार्ड बनवाकर पुलिस को गुमराह करेगा

केन्द्र की कांग्रेस सरकार जिस जालसाजी और चालबाजी पूर्ण तरीके से आधार कार्ड को हर शासकीय योजना में नाम, पते के लिये अनिवार्य कर जनता को आधार कार्ड बनवाने को मजबूर कर रही है, ताकि वह जनता की अधिकांश जानकारियों के समंक एकत्रित कर, विश्व की बड़ी बहुराष्ट्रीय कं., पूंजीपतियों को बेच कर हजारों करोड़ रु. कमाई कर रही है। बेशक यह सामंको की हजारों करोड़ की खरीद बिक्री में शासकीय खाते में तो एक पैसा भी नहीं जा रहा वरन् नंदन नीलकोणी को उन्हें ही इन आधार कार्ड्स पर पहली किश्त में एक मुस्त का 100 करोड़ अवश्य दिये गये थे। तो समाप्त हो ही गये साथ ही अभी तक 50 प्रतिशत लोगों के हाथ में 4-5 बार औपचारिकतायें पूरी करने के बाद भी यहां आधार कार्ड हाथ में नहीं आये, जबकि योजना को लागू किये 3 वर्ष से ज्यादा का समय गुजर चुका है। दूसरी और जनता को आधार कार्ड बनवाकर जनता को परेशान करने के लिए केन्द्र सरकार उसकी सभी योजनाओं यथा गैस वितरण, बैंक खाता खोलने, गैस का अनुदान खाते में जमा करने व अन्य योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार कार्ड को नाम पते के रूप में मांग रही है। निरंतस हजारों करोड़ रुपए खर्च कर पिछले 2-3 वर्षों से समाचार पत्रो में, सभी टीवी चैनलों पर विज्ञापन देकर धमका रही है। जिसका मूल उद्देश्य है भारतीय जनता का जैविक, समंक आर्थिक और सामाजिक समकों को एकत्रित कर सारे समकों को बहुराष्ट्रीय औषाधीय, चिकित्सीय, शृंगार सामग्री, खाद्य सामग्री, इलेक्ट्रानिक्स, फुटकर, व्यावसायिक कं. को उपलब्ध करवा कर उनकी भविष्य की व्यावसायिक आर्थिक नियोजन में सहयोग देना है। बेशक ये समंक जो इंटरनेट साइटों पर एकत्रित, सांकालित किये जा रहे हैं। सबसे पहले अमेरिकी सर्वर में ही पहुंचते है। जिसकी आशंका समय माया ने लगातार 2002 से 2013 तक प्रकाशित की और अपनी साइटों पर चढ़ाई थी कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जब से इंटरनेट का विस्तार होने लगा और अपंजीकृत आभासी या मृदु कार्यक्रमों या पायरेटेड साफ्टवेयर्स को लेकर कंम्प्यूटर चालकों को चेतावनी देने लगा तब ही यह सिद्ध हो चुका था कि उसकी हर विश्व के अरबों कम्प्यूटर्स ही हर बारीक से बारीक जानकारी इंटरनेट से जुड़े होने पर उसके पास पहुंच जाती है, जिसकी खबर अमेरिकी खुफिया एजेंसी के विद्रोही स्नोडन ने कर दी। अब जबकि आधार कार्ड का सारा डाटा इंटरनेट के माध्यम से ही केंद्रीय सर्वर पर भारत में एकत्रित होने से पूर्व अमेरिका में एकत्रित हो रही है दूसरी और चीन जैसे शत्रु हमारी साइटों को चाहे जब उलझा कर निकालते रहते हैं। फिर पाकिस्तानी भी भारतीय साइटों को उलझाने, रोकने और डाटा चुराने में शातिर और माहिर हैं।

वर्तमान में डाटा सेलिंग का व्यवसायी भी खरबों रुपए का हो चुका है। डाटा की जरूरत भारत में राजनैतिक पार्टीयों से लेकर सरकार के ठेकेदारों, मंत्रियों, दलालों, मोबाइल कं. से लेकर बहुराष्ट्रीय कं.तक सभी को भविष्य के नियोजन के लिये आवश्यकता है। गैस कं., बैंकों, आदि को जनता ने सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जो अपने बैंक खाता क्रं. और मोबाइल नं. दिये उसके दुष्परिणामों के रूप में सामने आया, कि कम्प्यूटर्स के माध्यम से जालसाज हैकरों ने आसानी से बैंक के खाते साफ कर दिये थे तो वे मामले हैं, जो सामने आ गये, परंतु 90 प्रतिशत जनता का सरकारी बैंको पर आज भी भरोसा है, जिनके वेतन खाते बैंकों से जुड़े नहीं है। वे 90 प्रतिशत लोग बिना आवश्यकता के बैंक ही नहीं जाते हैं। उनके खाते से यदि रकम साफ हो गई तो कौन जिम्मेदारी उठायेगा, जबकि ग्राहक को तत्काल में धन की आवश्यकता है। आधार कार्ड का सबसे ज्यादा लाभ जालसाज, चालबाज, ठग, अपराधी, आतंकवादी, बांग्लादेशी, चीनी, नेपाली और पाकिस्तानी घुसपैठियें कानूनी लाभ ले रहे हैं। इस बात को स्वयं सीमावर्ती पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वीकार किया है। वही हाल राजस्थान और गुजरात के पाकिस्तान से जुड़े क्षेत्रों के हैं। यहां पर भी ऐसे हजारों घुसपैठियों ने घुसकर जिसमें न केवल आतंकवादी संगठनों के सक्रिय और सुप्त कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या है, आसानी से कहीं भी कोई भी वारदात कर भाग कर दूसरे जिलों में जाकर आधार कार्ड बनवाकर स्थाई निवासी बनकर वहां पर ड्राइविंग, फूड, ड्रग, गुमास्ता आदि के लाइसेंस आदि प्राप्त कर पुराने आपराधिक रिकार्ड को कानूनी रूप से समाप्त करवा लेते हैं। ऐसे में कानून, पुलिस और न्यायालय को भी बता दी जाती है। आधार कार्ड साधारण आमजन के लिये भी पते, पहचान आदि के लिये भी कोई महत्वपूर्ण कानूनी संरक्षण प्रदान नहीं करता पर आम नागरिक को तो सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा बनना उसकी बाध्यता है, इसलिये उसने सरकारी विज्ञापनों आदि के लिये व सरकारी योजनाओं तथा राशन आदि प्राप्त करने के लिए बनवा लेता है। जिन्होंने आधार कार्ड बनवाकर बैंक आदि के खाते नं. व मोबाइल नं. देकर गैस कं. को दे दिये अब उनकी बाध्यता पहले रु. 1340 का फरवरी से रु. 1230 का गैस सिलेंडर लेना मजबूरी बन गया, देश के लाखों गैस उपभोक्ताओं के खाते अनुदान भी नहीं पहुंचा। यथार्थ में आधार कार्ड में आधारहीन है क्योंकि उसमें हर व्यक्ति के जन्म से लेकर कार्ड की तारीख तक का कोई इतिहास तो होता नहीं जो अपराधियों के उसने कहां-कहां रहकर कितने और किस प्रकार के अपराध किये। ठगी, चोरी, ड्रग, डकैती, बलात्कार, आदि को कर जहां से कार्ड बनवाया वहां किस नाम से और कैसे रह रहा है, किसी भी जिले के प्रशासनिक कार्यालय में जहां कार्ड बन रहे है, या अनॉलनाइन बनवाकर आसानी से वहां का स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र दे देगा, फिर यहां अपराध करेगा, यहां से भागकर दूसरी जगह जाकर दूसरे नाम से कार्ड बनवाकर कानूनी आधार लेकर आसानी से जीवन यापन कर लेगा। आधार कार्ड बनाने वाली सरकारी एजेंसी इस दोहरे, तिहरे आधार कार्ड को रोकने में सक्षम नहीं, फिर अपराधियों के पकड़े जाने पर उनके पास अलग-अलग स्थानों के अलग-अलग नामों के आधार कार्ड निकले जिसमें पुलिस स्वयं उलझ गई कि अपराधी का वास्तविक नाम पता क्या है, फिर जालसाजों ने अलग-अलग आधार कार्ड बनवाकर अलग-अलग जिलों में बैंकों से लोन लिये, सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठाया, घुसपैठियों ने भी आधार कार्ड की आधारहीनता का न केवल भरपूर उपयोग वरन् कार्ड बनते ही वो भारतीय नागरिक के भी हकदार होगा कि बेशक कांग्रेस ने पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसे लाखों बांग्लादेशियों को आधार कार्ड दिलवाकर उन्हें मताधिकार दे दिया जो उसकी उन राज्यों को जीत दिलाने को मददगार भी हुआ पर यही वोट पाने का लालच, असम, मिजोरम, काश्मीर को धधकाता रहता है। नंदन नीलणिकी इस योजना से उसने भले ही डाटा बेचकर रु. हजारों करोड़ कमा लिये हो, परंतु न केवल जनता के अरबों आधार कार्ड बनाने, उसका प्रचार-प्रसार करने में न केवल बर्बाद हो गये वरन् जनता को भी करोड़ो श्रम घंटो का नुकसान उठाना पड़ा।

साप्ताहिक समय माया

म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का, क्या औचित्य नहीं

निजी स्कूलों द्वारा ड्रेस और पुस्तकों में होती है भारी कमीशनखोरी

निजी शिक्षण संस्थाओं में साधनों का अभाव, फिर भी भारी शिक्षण व अन्य शुल्क, ड्रेस और पुस्तकों पर कमीशनखोरी के लिये निश्चित दुकानें

पूरे राष्ट्र में शिक्षण का गोरखधंधा भारी कमाई और लूट का न केवल पूरा व्यवसाय बन चुका है, वरन पूंजीपतियों, जालसाजों, भूमाफियाओं के लिये उन्हें गुणकीय अनुपात में कमाई और अय्याशी का अड्डा बन चुका है। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की अनेकों टिप्पणियों और दिशा-निर्देशों के बाद भी न केवल राज्य सरकारें उनके शिक्षा विभाग के मंत्री प्रधान सचिव, सचिवों से लेकर आयुक्तों, संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों से लेकर वहां बैठे बाबुओं वही हाल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और उसके अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय शिक्षा विद्यालयों और उनके अंतर्गत पंजीकृत प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में चारों तरफ भारी लूटपाट हर कदम पर की जाती है। शासन के दिशा-निर्देशों की धज्जियां उड़ाने के लिये उसके तोड़ तैयार रहते हैं। साथ ही जो शासन के अधिकारी यथा जिला शिक्षा अधिकारी, एडीएम, एसडीएम, जिलाधीशों को सभी ऐसे जालसाज स्कूल संचालक अपनी इन कारगुजारियों के लिये प्रवेश से लेकर ड्रेस बेचने, पुस्तकें बेचने, साधन विहीन होने के बाद भी जबकि न स्कूलों में ढंग का पीने का पानी, न खेलने का मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालायें, भौतिक रसायन, जीव विज्ञान, पौध विज्ञान आदि की सुविधायें न होने के बाद भी सबका शुल्क, भारी भरकम शिक्षण शुल्क, जबकि शिक्षकों के नाम पर यहां तक कि 8वीं, 10वीं पास शिक्षिकायें जिन्हें 6 घंटे का मात्र रु. 2000/- से 3000/- के वेतन मात्र काम के दिनों का। छुट्टी के दिनों में वेतन की भी छुट्टी जबकि विद्यार्थियों के पालकों से प्रवेश के समय ही सारे हरामखोर, जालसाज संचालक पूरे साल का 12 माह का शिक्षण शुल्क के साथ ही रु. 15 से 30 हजार व ज्यादा का खर्च बताकर किस्तों में वसूली शुरू कर देते हैं। प्रवेश से शुरु हुई ये कहानी आगे बढ़ते ही पुस्तकों और ड्रेसों पर आती हैं, जो कि स्कूल संचालकों की एक मुश्त मोटी कमाई का हिस्सा होने के कारण ये गिद्धों की फौज म.प्र.पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित पहली से 12वीं तक की हर विषय की पुस्तकों के विपरीत सारी पुस्तकों में से मात्र हिन्दी व एक दो विषय की पढ़ाने के अतिरिक्त अन्य सारी पुस्तकें निजी प्रकाशकों की पुस्तकें जो सामान्य तीन से 10 गुना महंगी होती हैं जिनमें इन्हें आसानी से 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन मिलता है चलवाते हैं। आखिर जब जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा करने के लिये मोबाइल लगाया तो उसने भी फोन नहीं उठाया। उसको एसएमएस भेजा तो भी उसने जून से ही फोन उठाना बंद कर दिये थे, अकेले इंदौर में ही पालकों से रु. 500 करोड़ की ठगी की गई, जहां पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकें रु. 25 से 70-80 रु. की कक्षा और विषय के हिसाब की थी जहां पहली से 5वीं तक की सभी विषयों की पुस्तकें रु. 100 से 200 की थी वहीं निजी की रु. 500 से रु. 1000/- की थी, जो स्कूल संचालकों की नीचता और डकैती के अनुसार थी, वहीं 6 से 10वीं तक की रु. 200 से 500/- तक की थी वहीं निजी स्कूलों में न्यूनतम रु. 500 से 2000/- की थी, वही हाल केंद्रीय मा.शि.मं. दिल्ली के अंतर्गत पंजीकृत स्कूलों का था, पूरे प्रदेश में ये ठगी का आंकड़ा रु. 5 से रु. 7000 करोड़ का था, ड्रेसेस के नाम पर, बेल्ट, बैच के मामले में भी अधिकांश स्कूली जालसाजों के गिरोह जानबूझकर सीधी, सादे कपड़ों की ड्रेस निर्धारित करने के विपरीत कालर, सामने के बटन की पट्टी, शर्टस, सलवार कमीज, स्कर्ट और पेंट आदि में बाहों और कलाई में दूसरे रंग की चेक्स, शर्टस जेब पर स्कूल बेच की कढ़ाई के नाम पर रु. 50 से 100 की शर्ट्स को तीन गुना से 5 गुना कीमतों पर पालकों के खास दुकान से खरीदने के लिये शासन के निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए मजबूर करवाया, साथ ही हर स्कूल में खेल का मैदान हो न हो, पर स्पोर्ट्स की एक ड्रेस अलग से खरीदवाई जाती है, जबकि 90% स्कूलों में कहीं कोई खेल का मैदान तो दूर 80% स्कूलों में प्रार्थना भी सड़कों पर ही करवाई जाती है, बेशक यह स्थिति केवल इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे म.प्र. के बड़े शहरों की ही नहीं वरन यह स्थिति अब छोटे नगरों, तहसीलों से लेकर गांवों की भी है, जहां वसूली तो हर तरीके से होती हैं, यह हुआ जून-जुलाई का महीना, फिर अगस्त से शुरू होगी वसूली 15 अगस्त के लिये वैसे जुलाई में भी गुरु पूर्णिमा के नाम से भी शुरु हो जाती है। तुलसी जयंती, फिर इस राष्ट्र में तो यथार्थ में हर दिन महापुरुष से लेकर त्योहारों, पिकनिक, टीचर्स डे, टीचर्स का जन्मदिन आदि के नाम पर भी हर माह रु. 100-200 रु. चिपका कर बच्चों से वसूल किये जाते हैं। न देने पर विद्यार्थियों को किसी न किसी बहाने प्रताड़ना, फेल करना, अनावश्यक सजा देना, मारपीट करना आदि तक सब झेलना पड़ता है, इसमें सबसे ज्यादा फजीहत होती है, उनके माता-पिताओं की, सरकार मानती है कि 70% बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ा पाते हैं। निजी विद्यालयों के बढ़ते चलन का कारण शासन की बत्तमीजी और जालसाजी पूर्ण नीतियां भी हैं जहां स्वयं शासन, उसके जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर विकासखंड अधिकारी, विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी तक सब ही जालसाजों, भ्रष्ट और डकैतों की फौज को केवल कागजी खानापूर्ति की आड़ में कमाई से मतलब होता हैं, तो दूसरी ओर वास्तविक शिक्षक उसकी निगाह में संविदा मजदूर जिसका वेतन मनरेगा के दैनिक मजदूरी करने वालों से भी कम साथ ही शासन की नीतियां भी, जिसमें अधिकांश समय शिक्षक कभी मानवों की जनगणना, कभी पशुओं की गणना, कभी गरीबी का, कभी बाल स्वास्थ्य व अन्य अनेकों कार्यों में उलझाये रखती हैं, जिससे वे यथार्थ शिक्षण कार्य नहीं कर पाते, इसलिये सरकारी विद्यालयों के शिक्षक ही बदनाम होते हैं। फिर मध्याह्न भोजन भी जो मोटा कमाई का जरिया होने के सशथ ही वास्तविकता में दूसरी तरफ शिक्षण कार्य को भी बाधित करता है, समय व्यर्थ व्यतीत हो जाता है, तो भी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी पद नहीं पाते, इससे निजी संस्थाओं को प्रोत्साहन मिलता है, फिर निजी संस्थायें शिक्षण की आड़ में पूर्णतः व्यवसाय ही होने के साथ भारी लाभ का सौदा बन चुका है, इस लाभ के सौदे में स्कूल के जालसाज मुखेरे संचालक अपनी कमाई का 2 से 5 % बांटने के साथ ही अपने स्कूल की शिक्षिकाओं को भी मान्यता प्राप्त करने से लेकर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति हजम करने, परीक्षा केन्द्र बनवाने परिणाम सुधारने तक में करते हैं। तो फिर किस सरकारी अधिकारी की औकात है कि ऐसे 95% जालसाज स्कूलों की लूट से बचाये, इन शिक्षण संस्थाओं में 80% शिक्षण संस्थाएं नेताओं, पार्षदों या उनके चेले-चपाटियों की है। वैसे भी अकेले इंदौर में 1100 से ज्यादा नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों में 95% स्कूलों में हैं, तो सभी जालसाज पर 200 से ज्यादा अधिक जालसाज वसूलीबाज माफिया हैं, जिन्होंने एक तरफ विद्यार्थियों व उनके पालकों को लूटा तो दूसरी तरफ सरकार से प्राप्त होने वाली छात्रवृत्तियों में भी आदिम जाति कल्याण विभाग के साथ मिलकर करोड़ों रु. की हेराफेरी कर हर वर्ष 50 से 100% छात्रवृत्ति तक विद्यार्थियों की फर्जी प्रमाण-पत्रों, फर्जी प्रवेश और अध्ययन के नाम से डकार जाते हैं। बेशक आदिम जाति कल्याण विभाग में बैठे धूर्त, मक्कारों, जालसाजों की बाबुओं से लेकर सहा. आयुक्त या जिलाधीश, लोकायुक्त, मंत्री आदि तक सबको यथा योग्य भेंट में से ही चढ़ाकर ये गोरखधंधा कर पा रहे हैं। इसलिये आदिम जाति के अरबों रु. के फर्जी छात्रवृत्ति वितरण कांड की जांच महीनों से अकेले इंदौर में ही लंबित है, जबकि यह घोटाला प्रदेश के सभी जिलों में 90% स्कूलों और निजी महाविद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक में हो रहा है यही कारण है कि हर निजी स्कूल और महाविद्यालय लाभ की दृष्टि से सफल सिद्ध होकर काली कमाई के बड़े स्त्रोतों में शामिल हो चुके हैं। यही कारण है कि अधिकांश जालसाज माफिया गिरोह अब स्कूल कालेज खोलकर लूट की स्थायी व्यवस्था करने में लगा है। जिसमें नेताओं से लेकर वल्लभ भवन स्तर तक के सचिवों से लेकर पुलिसिये जालसाज निरीक्षक भी शामिल हो चुके हैं। जिनके इंदौर से लेकर हर शहर में निजी स्कूल और महाविद्यालयों तक की लंबी श्रृंखला है, जिला शिक्षा अधिकारी, एडीएम और एसडीएम चाहें और ईमानदारी से युवा पीढ़ी के भविष्य के प्रति सोचें तो दिस. जन. और फर. माहों में हर वर्ष ऐसे स्कूलों में कक्षाओं में पहुंचकर शिक्षकों, शिक्षिकाओं के साथ प्रबंधन की और वास्तविक साधनों की जांच कर अप्रैल के बाद से हर वर्ष 20-25 % स्कूल बंद करवाकर जून-जुलाई में प्रवेश रोककर दूसरे स्कूलों में विद्यार्थियों को स्थानांतरित करवा दें ताकि स्कूलों का बहाना न मिल सकें। इंदौर के भागीरथपुरा में पार्षद मांगीलाल रेडवाल जो कभी कांग्रेस में कभी भाजपा में जब जहां पलड़ा भारी दिखा, बेपेंदी का लुढ़क लिया इसीलिये कि इसकी बहु दीपा रेडवाल जो मां शारदा विद्या मंदिर चलाती है, रु. 1000-2000 की शिक्षिकायें रखकर बच्चों को पढ़वाती हैं, बच्चों के माता-पिताओं से जबकि भागीरथपुरा निहायत गरीब क्षेत्र होने के बाद भी ड्रेस एक दुकान से ही खरीदो, किताबों के पैसे लेकर यह जालसाज बच्चों को वर्षभर पूरी कीताबें भी नहीं देती, पुस्तकों के पैसे लेकर पैसे हजम ही कर लेती हैं, अंदाज लगाया जा सकता है कि बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। दूसरी ओर कोई स्कूल छोड़ना भी चाहे तो ये भ्रष्ट जालसाज 20 जून से पहले स्कूल ही नहीं खोलेगी, समय भी कभी 12 बजे से पूर्व स्कूल में उपलब्ध नहीं होगी। बच्चों के माता-पिता को हड़काने-धमकाने की भी चालें चलती है, मार्कशीट लेने के पहले पूरी फीस जमा करो, साथ में छुट्टी की दो माह की फीस भी दो, टीसी मांगने पर रु. 250/- लेने के बाद भी 10-20 चक्कर कटवाना मामूली बात है। फिर हर माह रु. 100-200 जयंती, पिकनिक कार्यक्रम के वसूलना, यही कारण है कि पिछले 10 वर्ष में ही 5-7 मकान खड़े कर लिये गये, ये नमूना हर निजी स्कूल का है, परन्तु राजनैतिक पहुंच के चलते कोई कुछ नहीं बोल पाता, पढ़ाई 7वीं के बच्चे अखबार नहीं पढ़ पाते। सबको पास करना ताकि पुस्तकों के पैसे हजम करने की पोल न खुले, जबकि ऐसे 60% स्कूलों को मई-जून में हर हालात में बंद कर दिया जाना चाहिये।

विद्युत नियामक आय का योग देखकर जनता से लूट की व्यवस्था

बिजली कीमतों वृद्धि-लूट, भ्रष्टाचार का भार जनता पर

अधिकांश कार्य कमीशन के लिये ठेकेदारी पर हर एमडी को चाहिये हजार करोड़

मप्र में भाजपा के चुनाव जीतते ही, बिजली की ड्यूटी बढ़ा दी गई, ये तीसरी बार भाजपा को चुनाव जिताने का तोहफा था, शिवराज सरकार का जनता को, वास्तविकता में जब से विद्युत मंडल को वितरण, पारेषण, उत्पादन कं. में परिवर्तित में जब से विद्युत मंडल को वितरण, पारेषण, उत्पादन कं. में परिवर्तित किया और इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के धूर्त मक्कार आईएएस को जिसे विद्युत इंजिनियरिंग की एबीसीडी नहीं आती बैठाया गया है, तब से इन हरामखोरों की खरीदी जिसमें विद्युत की खरीदी से लेकर, तार बिजली के खंभों ट्रांसफार्मरों आदि में कमीशन खोरी ज्यादा बढ़ गई, जिसका दुष्परिणाम हर वर्ष में दो बार बिजली की कीमतें बढ़ाने के बाद भी घाटा बढ़ा कर जान बूझकर चार्टर्ड बनाम करप्ट एकाउंटेंटों की जालसाजियों से दिखाया जाता रहा है। एक तरफ मंडल के द्वारा तैयार चलाये जा रहे विद्युत उत्पादन केन्द्रों जिसमें जल और ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र है। जानबूझकर बिगाड़ कर बंद किये जा रहे है। ताकि 1 रु. यूनिट की बिजली को रु. 5 तक में खरीद कर कमीशन रु. 2 से 3 प्र.यु. का कमीशन डकार सके। रिलायंस, टाटा व अन्य से इसीलिये महंगी बिजली खरीदी जा रही है उनके प्लांटों को एक तरफ मप्र सरकार बैंकों से ऋण दिलवाने की गारंटी दे रही है तो दूसरी तरफ महंगी बिजली खरीदने के अनुबंध कर रही है, नव 13 के चुनावों में जनता को 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिये रु. 50000 करोड़ से ज्यादा की बिजली खरीदी गई जिसमें मंत्री राजेन्द्र शुक्ल और शिवराज ने मिलकर रु. 20000 करोड़ का कमीशन डकारा। जब विपक्ष के नेता ने जुलाई में रु. 22000 करोड़ की बिजली खरीद का आरोप लगाया तो उसे सिरे से नकार दिया गया, पुनः जीतने पर शुक्ला को इसी कारण ऊर्जा मंत्री बना दिया गया। दूसरी तरफ बिजली कं. में जो महाभ्रष्ट इंजिनियर सेवा निवृत्त हुये उन्हें न केवल सलाहकार बनाकर लूटने और भ्रष्टाचार के लिये पुनः रख लिया गया वरन मोटे वेतन देने के साथ उनकी या उनके रिश्तेदारों की फर्मों ने इन कं. में मेंटेनेस व सामान आपूर्ति के ठेकों पर कमीशन लेकर सौंप दिये गये, तीसरी तरफ एक ही स्थान पर भ्रष्ट जालसाज मीटर रीडरों जिसमें इंदौर के परदेशीपुरा जोन का नीतेश मंत्रिय जो उपभोक्ताओं के मीटर बंद करवाकर रु. 200 से 500 प्रति माह वसूली कर रहा है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से एक ही स्थान पर पाला जा रहा है। सूचना के अधिकार में प्राप्त जानकारी के अनुसार 20% कर्मचारी छोटे अधिकारी 10 वर्षों से ज्यादा समय से एक ही जगह जमे हैं। यही हाल पूरे पश्चिम क्षेत्र वितरण कं. के अंतर्गत 15 जिलों की हर जोन का है, जो अधिकांश स्वयं अपनी जेबे भरकर चोरी करवा रहे है और करोड़ों का कंपनियों का घाटा दे रहे है। जिसका पैसा भी एमडी तक जा रहा है और इस लूट और चोरी की भरपाई बिजली की कीमतें बढ़ाकर जनता से की जा रही है। विद्युत नियामक आयोग को काम ही आय के योग के अनुसार निर्णय देकर विद्युत कं. के हर दावे, पर आंख भींचकर हस्ताक्षर कर देना और कीमतें बढ़ाने का हल्ला मचने पर नाम बदल ड्यूटी बढ़ाने आदेश जारी कर देना है, इन आयोगों में बैठे शासन के ही पूर्व के अधिकारियों, आयुक्तों के पद पर बैठाकर 2 से 5 प्रतिशत जो करोड़ों में होता है, डालकर, आंख भींचकर आदेशों को हस्ताक्षरित करवा लिये जाते है। मप्र विद्युत नियामक आयोग में पूर्व का महाभ्रष्ट सेवानिवृत्त मुख्य सचिव राकेश साहनी को इसीलिए बैठाया गया है।

शिवराज जी जनता को गुमराह मत करो

शिवराज सिंह चौहान जनता को गुमराह कर रहे है जनता से न संवाद करने जाते है न आर्शीवाद मांगने जाते हैं । जनता को अपने ब्रान्डों का प्रचार करने जाते है,संवाद दोनों ओर से होता है एक तरफा नहीं और आशीर्वाद मांगने के लिए दाता के सामने झुकना पड़ता है,दाता की अपेक्षाऐं मालुम करनी पड़ती है ना कि डेढ़ करोड़ के रथ पर चढ़कर ,दूर से हाथ हिलाने से और ना छलकपट से ना हिन्दुओ के पिटवाने से ना पत्रकारों का माफिआओं के द्वारा मुंह बन्द कराने से । शिवराज जी जनता के बीच अपने राजनीतिक कमान्डरों की कंपनी के साथ स्वयं ही बोलते है जनता को सिर्फ अपने भाषण सुनाते है। ये संवाद वाला निष्पक्ष लोकतंत्र नहीं है ,बल्कि गुमराह करने वाला ब्रान्ड प्रचार तंत्र चला रहे है। ऐसा कार्य केवल मल्टीनेशनल कंपनियां की करती है। राजनीति कंपनी नीति से नही चलती। और ना ही उद्योग पतियों के दलाल बनने से ।

म.प्र.में आ-आ कर भाजपा के शीर्ष नेता पानी पी-पी कर मंहगाई के नाम पा कांग्रेस को कोस कर जनता को बेवकूफ समझ रहे है। जबकि सच यह है कि महंगाई की देन में कांग्रेस और भाजपा समान रूप से शरीक है । उदाहरण के तौर पर देखें शिवराज जी के उद्योगपति मित्र अनिल अंबानी के रिलायन्स ग्रुप के पास हरी ताजा सब्जी फल आदि बिक्री करने का लायेंसेस है इनके पास करीब 2000 गोदाम है प्रत्येक गोदाम में रखी औसतन 5 टन प्याज मानलें तो इनके पास 10000 (दस हजार) टन प्याज स्टोर है। इसके अलावा ईचौपाल,बेस्टप्राइज जैसी सैकड़ों कंपनियां स्टॉक करके बैठ गयी है । ऐसी ही अनेकों दैनिक खाद्य सामिग्री है जो इन कंपनियों ने स्टोर कर रखी है । भारत के किसानों ने देश के लिए भरपूर अन्न उगाया है परन्तु देश के शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता कंपनियों की ब्रान्डिंग करेगे तो मंहगाई को कौन रोकेगा।इनका तरीका भी बहुत निराला है पहले विरोध करते है बाद में उसी की ब्रांडिंग करके फलने फूलने का लाइसेंस दे देते है। और जनता को बेवकूफ समझकर भाषण देते है कि मंहगाई विपक्षी पार्टी की देन है। ये जनता को क्यो नहीं बताते कि महंगाई और भ्रष्टाचार हमारी साझी राजनीतिक दलाली की देन है। इन मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में व्यापार करने का लायसेंस केन्द्र सरकार ने दिया है तो उन्हें अपने राज्य में फलने फुलने का अधिकार कमीशन खाने के लिए राज्य सरकार ने । मानते है जनता सीधी है मगर अनजान नहीं है।

देश/विदेश तत्कालिक समाचारों के पीछे और उसके आगे के समाचारों के लिए क्लिक कीजिए

लोकतंत्र की संसद में काले गुरुवार का हंगामा पूर्व नियोजित षड़यंत्र था

क्या ऐसे ही अपराधी चाहिये संसद में

जनता द्वारा नोट में वोट का ही कमाल है, संसद के दर्पण में देखा जनता ने

भारत की संसद में गुरुवार दिनांक 13 फरवरी 2014 का दिन अपने देश का ऐतिहासिक दिन रहा, जिसमें कांग्रेस के पूर्व नियोजित षड़यंत्रों से अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह किस हद तक उतर कर कुकर्म करती है, उसका संसद आंधप्रदेश से चुन कर आये थे जिसमें लगदापलि, राजगोपाल ने साथी सांसदों की तरफ काली मिर्च स्प्रे उड़ा दिया, तो वेणुगोपाल ने माइक तोड़कर चाकू की भांति लहराया। संसद को ये पूर्व नियोजित षड़यंत्र कांग्रेस द्वारा रचा गया था। जिसकी रिहर्सल 11 बजे संसद के शुरू होने के साथ ही शुरू हो गई थी, संसद में सभापति की कुर्सी संभालते ही मीरा कुमार ने शांत रहिये बैठ जाइये से शुरू की। जिसका इशरा मिलते ही सांसदों ने हला मचाना शुरू कर दिया उन्हेंने एक घंटे के लिये संसद निलंबित की, पर 12 बजे शुरू होते ही जो घटना क्रम घटा-

12.02 स्प्रे छिड़का

वेणुगोपाल और कुछ सांसद नारेबाजी, हंगामा कर ही रहे थे कि विजयवाड़ा से निलंबित कांग्रेस सांसद एल राजगोपाल खड़े हो गए। उन्होंने महासचिव की मेज पर रखा पेपरवेट एक बॉक्स में दे मारा। जोर की आवाज हुई तो अफरा-तफरी मच गई। फिर राजगोपाल ने अपनी जेब से गुलाबी रंग की बोतल निकाली और हंगामा कर रहे सांसदों पर छिड़क दी। इस बोतल में मिर्च स्प्रे था। करीब एक मिनट तक वे इसे छिड़कते रहे।

12.04 अफरा-तफरी

स्प्रे से निकले लिक्विड के संपर्क में आते ही सांसदों को खासी होने लगी। वे सांस नहीं ले पा रहे थे। उनकी आंखो में त्रीव जलन हो रही थी। अध्यक्ष मीरा कुमार को भी खांसी हुई। तीन कांग्रेसी सांसदों विनय पांडे, पूनम प्रभाकर और बलराम नाईक की स्प्र से तबीयत बिगड़ी। वे सदन के गेट की ओर भागे। बाद में उन्हें एंबुलेंस में राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया।

12.05 चाकू निकाला

जब तक राजगोपाल को मार्शल काबू में करते, तब तक कुछ सांसदों ने राजगोपाल पर लात-घूंसों से हमला कर दिया। इसी बीच वेणुगोपाल अपने हाथ में धातु की वस्तु लहराते नजर आए। संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने इसे चाकू बताया, जबकि वेणुगोपाल उसे माईक बता रहे है।

12.06 पर बिल पेश कर उसको ध्वनियत से पारित कर दिया। इससे स्पष्ट है कि भविष्य में भी संसद में किसी भी बिल जैसे कि लक्षित हिंसा अधिनियम तो संसद में पिछले दस वर्षो से ज्यादा समय से है, जो स्पष्टतः हिन्दुओं की पूरी कौम को नष्ट करने केलिए उन्हें पहले कानूनी तरीके से फंसा कर पुरुषों को जेलों में डालकर हिन्दू महिलाओं को मुस्लिमों की रखैल बनाकर रखने और जीने पर मजबूर करेगा बाद में 30-40 वर्ष में पूरी हिंदू कौम का सफाया कर दिया जायेगा ताकि कांग्रेस की सत्ता निर्वाच रूप से इस देश को लूटती खसोंटती रहे, जैसा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस के कुकर्मो के इतिहास में दर्ज घटनायें।

22 जुलाई 2008 कैश फॉर वोट

परमाणु करार मामले में लोकसभा में विश्वासमत के दौरान भाजपा के तीन सांसदों अशोक अर्गल, राजस्थान के महावीर भागोरा और फग्गन सिंह कुलसे ने एक करोड़ रुपए के नोटों की गड्डियां लहरा कर सनसनी फैला दी थी।

20 सितम्बर 2013

उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन था। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर पक्ष और विपक्ष के विधायक एक-दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे।

12 दिसम्बर 2011

ओडिसा विधानसभा में कुर्सिया चली तो महाराष्ट्र की विधानसभा में कपास की गठाने फेंकी गई।

11 फरवरी 2014

जम्मू-कश्मीर विधानसभा दो दिन पहले ही मंगलवार को जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में मर्यादा को तार-तार किया गया।

यह इतिहास सिद्ध करता है कि कांग्रेस अपने स्वार्थो को पूरा करने के लिए किस हद तक नीचता पर उतरती है। कांग्रेस को कभी राष्ट्रहितों और जन कल्याण से सरोकार नहीं रहा उसे अपनी कमाई और सत्ता सुख के लिये वो कभी भी कुछ भी करती रही है और करती रहेगी।

मोदी प्रधानमंत्री, तो सब बहुराष्ट्रीय कं. की कठपुतली

पेज 1 का शेष

कल तक जो भाजपा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कं. के हितों को साधन और न्यूनतम विक्रय कर चुकाने, विक्रय कर को राज्यों के हाथों से निकालकर केंद्रीय सत्ता में केन्द्रित करने वाले माल व सेवाकर या गुड्स एड सर्विसेज टैक्स जीएसटी का विरोध कर रही थी, उसका मोदी ने राष्ट्र की सत्ता में पहुंचने से पहले ही आंख भींचकर लागू करने की बात करने लगा। पूंजीवाद अनादिकाल से बाजारवाद के चलन के साथ ही जनसामान्य के घोर शोषण, कुंठा, भूख और गरीबी का कारण भी रहा है, फिर इसी बाजारवाद का परिणाम थी ईस्ट इंडिया कं. की गुलामी। मोदी और उनकी भाजपा वर्तमान में कांग्रेस से आगे बढ़कर पूर्णतः पूंजीपतियों की रखैल बनकर, कमीशन डकारकर सारे राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों जिसमें खदानों, बिजली, पानी, सड़कों आदि को आगे बढ़कर टाटा,-अडानी, अंबानी, मित्तल, बिरला को सौंपने और बदले में मोटा कमीशन व हिस्सेदारी डकार जनता का शोषण करवाने पर तुली है, जिसके उदाहरण कोल घोटाले में मप्र की भाजपा सरकार में जेपी व अन्य की संलिप्तता से जनता के सामने आई कि किस प्रकार कं. 350 करोड़ से ज्यादा की लेनदारियों को बलाये ताक रखकर इन कं. को कोल ब्लॉक्स आवंटित कर दिए गए और जो कोयला उत्खनन रु. 5000/- प्रति टन पर जा सकता था उसे रु. 1028 प्रति टन की रायल्टी पर इन जालसाज पूंजीपतियों जेपी एसोसिएट्स आदि को सौंप दिया गया।

वही हाल मोदी ने गुजरात में भी किया, स्वाभाविक है यदि मोदी के इस धुआंधार प्रचार और विपक्ष में दमदार उम्मीदवार के अभाव में मोदी प्रधानमंत्री बन ही गया तो राष्ट्र पूर्णतः इन बहुराष्ट्रीय कं. की गिरफ्त में होगा सारे प्राकृतिक राष्ट्रीय संसाधनों को उनके लाभ और इनके कमीशन के लिये गिरवी कर दिया जायेगा, गरीबों के आंसू पोंछने और हिंदुओं का संरक्षण करने वाली पार्टी का दंभ भरने वाली भाजपा का दोहरा चरित्र हर भाजपा शासित राज्यों में पूरे राष्ट्र की और विश्व की जनता तरीके से देख समझ रही है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 06 के दुष्परिणाम और बहुराष्ट्रीय कं. की गुलामी के इस कानून जो राष्ट्र के 5 करोड़ से ज्यादा किसानों, छोटे व्यापारियों और खाद्य वस्तुओं के निर्माता, पेकर्स आदि को बेरोजगार कर देगा के विरूद्ध समय माया पिछले 7 वर्षो से लगातार प्रकाशन करने के कारण केन्द्र सरकार इस अधिनियम को 2011 तक लागू नहीं कर सकी, परंतु अन्ना के आंदोलन को 23.7.11 का 16.08.11 से करने की घोषणा की आड़ में समय पाकर केन्द्रीय सरकार ने 5 अगस्त 11 से लागू कर दिया और 4 अगस्त 12 तक पंजीयन करवाने को खाद्य व्यापारियों, फैक्ट्रीयों, ठेले वालों, खोमचो, चाय वालों तक को पंजीयन अनिवार्य रूप से करवाने की छूट दे दी जिसे, भाजपा की सरकारों वाले राज्यों में भाजपा ने शक्ति से लागू कर खुलकर उसके खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से लेकर उनके आयुक्तों ने भी बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के बदले करोड़ों रुपए महीने की उगाही कर मुख्यमंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्रियों ने धन बटोरा बाद में उसे तीन किश्तों में 6-6 माह के लिये बढ़ाया गया, अंतिम किश्त में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने। 13-14, जन 14 को वर्ष भर के लिये बढ़ाया परंतु मप्र के मु.मं. शिवराज, छग के मुख्यमंत्री रमन बैस, गुजरात के मोदी ने पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों को खुश करने के लिये और वसूली करने के लिये मात्र 6 माह भी 5 फरवरी 12 को बढ़ाया। तक तक सारे भाजपा के मुख्यमंत्रियों और उनके स्वा. मंत्रालयों ने अरबों रु. गरीब सड़क पर बैचने वाले ठेले, चाय वालो, दूध वालो से न केवल पंजीयन करने वालों से वसूले वरन् उन छोटे व्यापारियों, किसानों, सड़क पर सब्जी बैचने वालो तक से वसूली के साथ ही उन छोटे व्यापारियों को डाटा एकत्र कर बहुराष्ट्रीय कं. को मोटे कमीशन के बदले में भेंट कर दिया गया। अर्थात मोदी या भाजपा की सरकार बनते ही इस खाद्य सुरक्षा व मानक अधि.06 को लागू कर, गरीब व मध्यम वर्गीयों के को शोषण के लिये खुला छोड़ देंगे।

यथार्थ में जब भाजपानीत राजग की सरकार थी केंद्र में केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने शासकीय उपक्रमों, में निवेशीकरण के चलते अरबों रु. का कमीशन डकार बड़े-बड़े उद्योगपतियों को केन्द्र शासन के उपक्रमों चालकों, एनटीपीसी, मार्डन फूड जैसे हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियों वाले लाभ में चलने वाले उपक्रमों के शेयर्स बेचकर दूसरी कंपनियों यथा अंबानी, टाटा आदि को सौंप दिया जिसमें आईटीसी हिंन्दुस्तान लीवर, बहुराष्ट्रीय कं. थी।

इस इतिहास से यह भविष्य में होना निश्चित है, किए भाजपाई मुखेरे जानवरों की पार्टी मोदी की अगुवाई में चुनाव जीतकर भले ही मोदी को प्रधानमंत्री बनाये न बनाये परंतु सत्ता में आते ही इस राष्ट्र की मिश्रित अर्थव्यवस्था को पूर्णतः नष्ट भ्रष्टकर इसे पूर्णतः पूंजीवादी राष्ट्र बना देगी, जिसमें सड़के, बिजली, पानी से लेकर राष्ट्र के सभी प्राकृतिक संसाधन भी इन राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कं. के कब्जे में सौंपकर मोटा कमीशन हजम करेंगे।

साप्ताहिक समय माया

अखिल भारत हिन्दू महासभा

हिन्दु, हिन्दुत्व और हिन्दु राष्ट्र के लिये 1830 से प्राण पण से समर्पित

:: चुनावी घोषणा पत्र ::

- महंगाई नियंत्रण हेतु खाद्य वस्तुओं का वायदा व्यापार, सट्टा आदि के एमसी डेक्स और एनसी डेक्स तत्काल बंद करवाया जायेगा। कार्पोरेट सेक्टर को खाद्य वस्तुओं के स्टॉक पर 40% से ज्यादा बैंक ऋण नहीं दिया जाएगा।
- हर वर्ष 5% सरकारी नौकरियों में परीक्षाओं से भर्ती होगी, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सकें, अगले 5 वर्ष में एक करोड युवा भर्ती किये जायेंगे ।
- भ्रष्टाचार दूर करने हेतु हर वर्ष 4% भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को हटाया जायेगा।
- मोबाईल फोन्स में होने वाली प्रतिदिन हजारों करोड की सफेद पोश डकैती को रोकने के तत्काल तंत्र विकसित किया जायेगा ।
- डीजल, पेट्रोल, गैस ईधन पर केन्द्रीय करों को घटाकर 20% व राज्य करों को 20% की अधिकतम सीमा में रख, पेट्रोल पंपों पर होने वाली लूट, मिलावट कम नाप को रोककर 58 ऑक्टेन का पेट्रोल उपलब्ध करवाएंगे। रू.50/- लीटर पेट्रोल, रू.40/- प्रति. लीटर, रू.40/- लीटर गैस उपलब्ध कराई जायेगी ।
- बिजली, पानी, सडकों का निजीकरण, तत्काल सभी सेवाओं को राष्ट्रीयकृत कर रोका जायेगा ।
- किसानों को प्राकृतिक आपदा में बर्बादी पर उनकी लागत और मजदूरी जोडकर 100% वापसी सुनिश्चित की जायेगी ।
- खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 06 को तत्काल समाप्त किया जायेगा ताकि खाद्य वस्तुओं पर बहु राष्ट्रीय कंपनी की डकैती और 5 करोड लोगों का भविष्य में बेरोजगार होने से रोका जा सकें व मंहगाई पर नियंत्रण किया जा सके ।
- 12 वीं तक की स्कूली शिक्षा को निःशुल्क और रोजगारोन्मुखी बनाया जायेगा ताकि आगे की पढाई के लिये विद्यार्थी माता-पिता पर बोझ न बने, स्वरोजगार दिये जायेंगे ।
- पत्रकारिता से जुडे हर व्यक्ति को कार्य के दौरान दुघर्टना पर मृत्यु में रू. 10 लाख का बीमा, चिकित्सा के लिये रू. 2 लाख का बीमा, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं को न्यूनतम रू. 25,000/- के मासिक विज्ञापन ।
- विघुत हीन गांवों में सौर, पवन, उर्जा, गोबर कचरे व 12मासी नदियों के किनारे बसे गांवों की लागत पर विघुत व्यवस्था की जायेगी ।
- सूचना अधिकार अधि. 05 की धारा 4 के अंतर्गत 17 बिन्दुओं की शासकीय विभागों की सारी जानकारी ऑन लाईन उपलब्ध करवाकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जायेगी।
- ऑयोडीन नमक जैसे जनता को लूटने वाले सारे कानून तत्काल समाप्त किये जायेंगे ।
- ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने ग्रामीणों को गांवोंमें लघु व कुटीर उद्योग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी ।
- सरकारें पूंजीपतियों की रखैल बन, वार्षिक बजट, कानून बनाकर जनता का शोषण करने के विरूद्ध संसद से सडक तक हर स्तर पर प्रतिरोध करेंगे ।
- खेलों के विकास व जनता को स्वास्थ्य व निरोगी बनाये रखने के लिए नगरों व गांवों के हर वार्ड में आंतरिक व बाह्य खेल परिसरों की स्थापना सुनिश्चित की जायेगी।
- सभी शासकीय कर्मियों की हर 3 वर्ष में परीक्षाओं से पदोन्नतियां व अन्य लाभ सुनिश्चित किये जायेंगे।

प्रेरणास्त्रोत
वीर विनायक दामोदर सावरकर

प्रदेशाध्यक्ष
शिवकांत शुक्ला
मो. 98260 46649

इंदौर लोकसभा से हिन्दु महासभा के प्रत्याशी

अजमेरा एस.प्रवीण कुमार

(प्रधान सम्पादक, सा. समय माया समाचार पत्र)

और विस्तार के लिये देखें और पढ़ें (www.samaymaya.com) को अपना अमूल्य मत देकर विजयी बनाकर अपना और राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित,समृद्ध और गौरवशाली बनायें।

निवेदकः राहुल मंडलोई, सत्यनारायण तिवारी, अर्पण जैन (खबर हलचल), सावन सोनी, श्रीमति अनिता भदौरिया, अर्जुन पंवार, रीतेश मूसले, यशवंत भदौरिया

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 94256 37958, इंदौर कार्यालय- 0731-2015827, मोबा. 94251 25569